वूमेन एक्सप्रेस

www.womenexpress.in

Email: thewomenexpress@gmail.com

Women Express tv

● वर्ष 7 ● अंक 255 ● हिन्दी दैनिक ● नई दिल्ली गुरूवार 12 नवम्बर 2019 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य 1 रूपया ● डाक पंजीयन DL (E)-20/5448/2017-19

नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पास

राज्यसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग, बिल के पक्ष में पड़े 125 वोट, विपक्ष में 105

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली। संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताडऩा के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के मुसलमान भारतीय नागरिक थे, हैं और बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में खासी कमी आयी है। शाह ने कहा कि विधेयक में उत्पीडऩ का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। शाह ने इस विधेयक के मकसदों को लेकर वोट बैंक की राजनीति के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए देश को आश्वस्त किया कि यह प्रस्तावित कानून बंगाल सहित पूरे देश में लागू

होगा। उन्होंने इस विधेयक के संविधान विरूद्ध होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संसद को इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार स्वयं संविधान में दिया गया है। उन्होंने यह भी उम्मीद जतायी कि यह प्रस्तावित कानून न्यायालय में न्यायिक समीक्षा में सही ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को चिता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं और बने रहेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना के तीन सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। बता दें कि लोकसभा में बिल का समर्थन करने को लेकर महाराष्ट्र में उसके साथ सरकार चला रही कांग्रेस ने शिवसेना से ऐतराज जताया था। इसके अलावा बीएसपी के दो सांसदों ने भी वोटिंग का बहिष्कार किया।

सोनिया गांधी ने बताया काला दिन

नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह भारत के इतिहास में काला दिन है। इसके अलावा बिल पर वोटिंग का बायकॉट करने वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

विपक्ष ने भेदभाव करने वाला बिल बताया

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और जिसके बाद सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला बताया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि इस बिल में केवल तीन देशों का और सिलेक्टिव धर्मों का ही चुनाव क्यों किया गया है। आजाद ने कहा कि भूटान, श्री लंका और म्यांमार में भी हिंदू रहते हैं और अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ भी अन्याय हुआ लेकिन उनको विधेयक के प्रावधान में शामिल नहीं किया गया है।

शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैरमुस्लिम शरणार्थियों को इस बिल में नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इस बिल में इन तीनों देशों से आने वाले हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का प्रस्ताव है।

धर्म के आधार पर न बंटता देश तो न आता बिल

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा न होता तो यह बिल न लाना पड़ता। अमित शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि आखिर जिन लोगों ने शरणार्थियों को जख्म दिए हैं, वही अब जख्मों का हाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि कोई सरकार पहले ही इस समस्या का समाधान निकाल लेती तब भी यह बिल न लाना पड़ता।

निर्भया के दोषियों को मेरठ का जल्लाद देगा फांसी !

(विशेष संवाददाता)

लखनऊ । निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर चढ़ाने के लिए यूपी के मेरठ से जल्लाद जाएगा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यूपी जेल के डीजी को पत्र लिखकर जल्लाद उपलब्ध कराए जाने की गुजारिश की थी।

जिस पर जेल मुख्यालय ने मेरठ के जल्लाद को भेजने की मंजूरी दे दी है और इस संबंध में बुधवार को ही तिहाड़ जेल प्रशासन को जवाब भेज दिया गया है।

हालांकि, तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से भेजे गए पत्र में इस बात का जिक्र नहीं है कि किसे फांसी दी जानी है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि निर्भया के गुनाहगारों को ही सजा दी जाएगी।

डीजी जेल आनन्द कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कुछ मृत्युदंड पाए अभियुक्तों को फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए जल्लाद की मांग की गई थी।

यूपी में वर्तमान में सिर्फ लखनऊ और मेरठ में दो जल्लाद उपलब्ध हैं। मेरठ के जल्लाद को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में मेरठ अधीक्षक को सूचित कर दिया गया है। साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन को भी उनके पत्र के जवाब में पत्र भेज दिया गया है।

पांच हजार रुपये महीना मिलता है जल्लादों को

फांसी चढ़ाने वाले जल्लादों को बतौर रिटेनर रखा जाता है। इन्हें हर माह 5000 रुपये दिया जाता है। पहले यह 3000 रुपये होता था।

बाद में इसे बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। इन्हें सिर्फ फांसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही बुलाया जाता है।

भारत ने वेस्टइंडीज को किया चारों खाने चित

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली। मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाईवोल्टेज टी20 मैच खेला गया। तीन मैचों की टी20 सीरीज का ये आखिरी और सीरीज डिसाइडर मैच था, जिसे भारतीय टीम ने 67 रनों के बड़े अंतर से जीता। इस मुकाबले में मिली जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की इस टी20 सीरीज को 21 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद अब दोनों टीमें रविवार को वनडे सीरीज की शुरुआत करेंगी। इस बड़े मुकाबले में वेस्टइंडीज टीम के कप्तान किरोन पोलार्ड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। वहीं, जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल

राहुल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। बाकी का काम कप्तान विराट कोहली ने कर दिखाया। इन तीनों की शानदार पारियों के दम पर भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 240 रन बनाए, जिसमें राहुल ने 91, रोहित ने 71 और विराट ने 70 रन का योगदान दिया। 241 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम शुरुआत से ही घुटने टेक गई। सलामी बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। यहां टीम को एविन लुइस की भी कमी खली जो चोट के कारण बल्लेबाजी नहीं कर पाए। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 20 ओवर में 173 रन पर रोक दिया।

इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम के 8 विकेट भी गिर गए। इस तरह भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 67 रनों के अंतर से जीतकर सीरीज का शानदार समापन किया। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान पोलार्ड ने 69 रन की तूफानी पारी खेली। 241 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका ब्रैंडन किंग के रूप में लगा जो 5 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। शमी ने भारत को दूसरी सफलता लेंडल सिमंस के तौर पर दिलाई और उन्हें सात रन के स्कोर पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। तीसरा विकेट निकोलस पूरन के रूप में गिरा जो बिना खाता खोले दीपक चाहर की गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। मेहमान टीम को चौथा झटका शिमरन हेटमायर के रूप में लगा जो 24 गेंदों में 41 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए।

भाजपा ने बिल के बहाने साधे एक तीर से कई निशाने

भाजपा ने बिल के बहाने साधे एक तीर से कई निशाने

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली। भारतीय संसद में बुधवार का दिन फिर एक बार नया इतिहास लिखने के लिए जाना जाएगा। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को जाएगा। इस जोड़ी ने कश्मीर में धारा370 हटाने के बाद बुधवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करा लिया। इस फैसले से सत्ताधारी दल भाजपा गदगद है। देश का एक बड़ा हिस्सा भी मोदीशाह के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। इस ऐतिहासिक विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताडऩा के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

सूत्रों की माने तो नागरिकता संशोधन बिल के बहाने मोदी सरकार एवं भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साध रही है। पहले सरकार ने अपने परंपरागत हिन्दू वोट बैंक को एक साथ रखने के साथसाथ अपना 50 लाख से ज्यादा का वोट बैंक बढ़ा लिया। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1 लाख गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसे में अगर इन शरणार्थियों में आधे भी मतदाता होंगे तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। साथ ही भाजपा की पुरानी कट्टर हिन्दू समर्थ छवि एक बार और मजबूत होगी। बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल जिस तरह से कैबिनेट में आया और आनन फानन में लोकसभा में पास किया गया और बुधवार की रात राज्यसभा में मंजूरी मिली उससे एक बात

साफ है कि मोदी सरकार इस बिल को पास कराने की जल्दी में थी। हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट न आने को लेकर भी भाजपा परेशान थी। जबकि, झारखंड में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा एक महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में भी स्थिति खराब न हो और भाजपा फिर से मजबूत हो इसके लिए यह बिल कारगर साबित हो सकता है। वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते सरकार चौतरफा घिरी हुई है, ऐसे में भाजपा का राष्ट्रवादी एजेंडे का दांव बचाने में कामयाब होगा। आने वाले समय में पार्टी इस विधेयक और उसके फायदों के बारे में गांवगांव तक पहुंचाना चाहती है, ताकि एकएक व्यक्ति को इस ऐतिहासिक बिल की जानकारी हो सके।

भाजपा ने पीएम, शाह और सांसदों को दी बधाई

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया। साथ ही विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद किया। नड्डा ने कहा कि यह संशोधित विधेयक (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) में धार्मिक उत्पीडऩ का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन के जीने का अवसर प्रदान करेगा। लंबे समय से अन्याय का दंश झेल रहे इन अल्पसंख्यक विस्थापितों को आज मोदी सरकार के महती प्रयास से न्याय प्राप्त हुआ है। यह विधेयक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा।

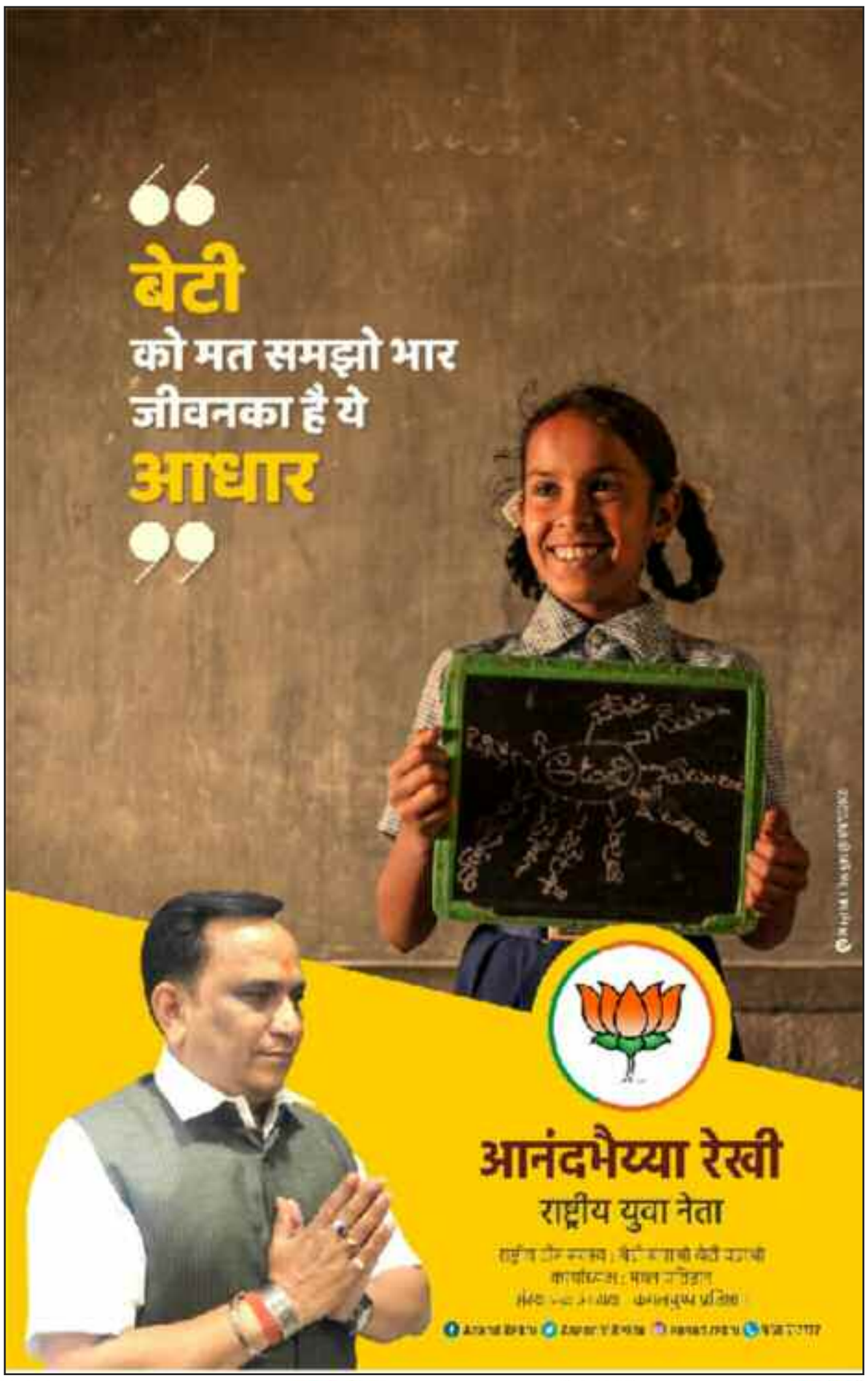

गुवाहाटी में कर्फ्यू, त्रिपुरा में सेना बुलाई गई

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन

(विशेष संवाददाता)

गुवाहाटी/अगरतला। नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच असम के गुवाहाटी में बुधवार को अनिश्चिकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया जबकि त्रिपुरा में सेना बुलाई गई है और असम में सेना की टुकड़ी को तैयार रहने को कहा गया है। इस बीच, ताजा समाचारों के अनुसार, संसद ने आज रात इस विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा में इसे सोमवार की देर रात पारित किए जाने के बाद आज राज्यसभा ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी। शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच असम के 10 जिलों में बुधवार की शाम सात बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को स्थगित रखा जायेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) कुमार संजय कृष्णा द्वारा जारी एक अधिसूचना के

अनुसार लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। शरारती तत्वों के शांति को भंग करने के प्रयासों को विफल करने के लिए पूरे त्रिपुरा राज्य में भी मंगलवार की अपराह्न दो बजे से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं पहले से ही बंद हैं। त्रिपुरा में इंटरनेट सेवाएं बुधवार को दूसरे दिन भी बंद रहीं। अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट सेवाएं बृहस्पतिवार तक स्थगित रहेंगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन और बस सेवाएं भी रोकी गई हैं। शुरूआत में असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने बताया था कि कर्फ्यू बृहस्पतिवार की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि उन्होंने बाद में बताया कि कर्फ्यू अनिश्चिकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। शिलांग में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि त्रिपुरा में बुधवार को सेना बुला ली गई और असम में सेना की टुकडियों को आज रात ही तैनात कर दिया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि सेना की एकएक टुकड़ी को त्रिपुरा के कंचनपुर और मनु में तैनात किया गया है जबकि गुवाहाटी में आज रात तक सेना तैनात हो जाएगी। सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पी खोंगसाई ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सेना की दो टुकडियां तत्काल गुवाहाटी जा रही हैं और वे जल्द ही पहुंच जाएंगी।

जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि ये टुकडियां शहर में पहुंचते ही तैनात कर दी जाएंगी और ये फ्लैग मार्च करेंगी। हालांकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अगरतला में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य के किसी भी स्थान पर सेना तैनात नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि असम राइफल्स की टुकडियों को हिंसाग्रस्त धलाई जिले में तैनात रखा गया है।

एक नजर

पूर्वोत्तर में अर्द्धसैनिक बल के पांच हजार जवान भेजे

नयी दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अर्द्धसैनिक बल के 5000 जवानों को विमान से भेजा। अधिकारियों ने बताया कि संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के खिलाफ वहां हो रहे विरोधप्रदर्शन के सिलसिले में कानूनव्यवस्था बनाए रखने के लिए जवानों को वहां भेजा गया है। कश्मीर से करीब 20 कंपनियों (2000 जवानों) को वापस बुलाया गया है जहां उन्हें पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र के निर्णय से पहले भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि शेष 30 कंपनियों को अन्य स्थानों से पूर्वोत्तर राज्यों में भेजा गया है। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान शामिल हैं।

सेना गया स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी बंद करेगी

नयी दिल्ली। भारतीय सेना बिहार के गया स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) बंद करेगी। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि क्षमता से कम इस्तेमाल की वजह से इसे जारी रखना संभव नहीं है। सैन्य अधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में कहा गया कि ओटीए को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह योजना के मुताबिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। अधिकारी के मुताबिक मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह संस्थान 2011 से तकनीकी आधार पर प्रवेश योजना और विशेष कमीशन अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। अब इन कैडट अधिकारियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओटीए गया, ओटीए चेन्नई और आईएमए देहरादून के बाद तीसरा कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमी है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। मौजूदा समय में ओटीए गया में 250 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जबकि इसकी क्षमता 750 अधिकारियों की है। बिहार के औरंगाबाद से सांसद ने संसद में बजट सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि ओटीए गया के बंद होने से स्थानीय अर्थव्यस्था को नुकसान पहुंचेगा।

संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने रूस के नौसैनिक पोत भारत पहुंचे

नयी दिल्ली। भारत और रूस की सशस्त्र सेना के तीनों शाखाओं के सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए रूसी नौसेना के तीन पोत गोवा पहुंच गए हैं। यह जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि आईएनडीआरए 2019' सैन्य अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और समझ विकसित करना है ताकि सुरक्षा की साझा चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, आईएनडीआरए 2019' में हिस्सा लेने के लिए रशियन फेडरेशन नेवी (आरयूएफएन) के पोत यारोसलाव मुद्री, विक्तर कोनेत्सकी और एलाइना दस दिसम्बर को गोवा पहुंचे।'' दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच गोवा के तट पर 10 से 19 दिसम्बर तक अभ्यास होगा। आईएनडीआरए शुरू में भारत और रूस के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के तौर पर 2003 में शुरू हुआ। अब यह अभ्यास दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच होता है। मंत्रालय ने बताया कि 18 दिसम्बर को थल सेना के अभ्यास में भारतीय थल सेना घटक प्लाटून तैनात कर रही है जबकि भारतीय वायुसेना की तरफ से अभ्यास में एसयू30एमकेआई और जगुआर सैन्य विमान, एमआई 17 हेलीकॉप्टर और अवाक्स विमान हिस्सा लेंगे।

दिल्ली सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना स्थगित

रेलवे ने ट्रेन उपलब्ध कराने से किया इन्कार

(लोकेश निरवाल)

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रेलवे से किन्हीं कारणों से ट्रेन उपलब्ध नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। रेलवे ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि फिलहाल ट्रेन उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ट्रेन की व्यवस्था होती है, यात्रा शुरू करा दी जाएगी।

लिहाजा रेलवे ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए समझौते के मुताबिक ट्रेन उपलब्ध करा पाने में फिलहाल असमर्थता जताई है। दिल्ली सचिवालय में बुधवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बहुत सफलता पूर्वक चल रही है। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने के लिए योजना शुरू की गई है। दिल्ली सरकार मीडिया के माध्यम से तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को आवश्यक सूचना देना चाहती है। तीर्थ यात्रा योजना रेलवे के सहयोग से चल रही थी। रेलवे के साथ दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना के लिए समझौता किया है।

रेलवे ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है कि वे अभी तीर्थ यात्रा योजना के लिए ट्रेन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके उन तमाम लोगो को जानकारी देना चाहती है कि फिलहाल यह यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी। यह यात्रा तब तक स्थगित रहेगी, जब तक रेलवे ट्रेन

उपलब्ध नहीं कराता है या फिर दिल्ली सरकार कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती है।

हमें उम्मीद है कि जो भी तकनीकी दिक्कत होगी, रेलवे उसका पता लगा कर वापस इस यात्रा की शुरुआत करेगी। इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों से बात चल रही है। अगर हम डेटा देखें तो अब तक 12 रूट्स पर दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है।

इसमे से सबसे ज्यादा पापुलर 10 रूट्स हुए हैं। अब तक 32828 यात्री यात्रा कर चुके हैं। अब तक कुल 63432 लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इसमे से 32828 लोग यात्रा कर चुके हैं। 30877 यात्री अभी पेंडिंग (लंबित) लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इस योजना के तहत पहली ट्रेन 12 जुलाई को यात्रियों को लेकर गई थी। तब से लेकर अब तक 34 ट्रेन यात्रियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा चुकी हैं और अभी 30 ट्रेन अगले दो महीने में जाने वाली थीं।

इसमे से 18 ट्रेन इसी महीने जाने वाली थीं। इसमे से कुछ ट्रेन गई भी हैं और बाकी की ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी है। अभी 12 ट्रेन दिसम्बर और 18 ट्रेन जनवरी में जानी थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे की तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित की जा रही है। हम रेलवे के अधिकारियों से बात करेंगे और उम्मीद है कि इसका जल्द कोई समाधान निकल जायेगा।

रेलवे ने ट्रेन उपलब्ध न कराने का नहीं बताया कारण

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ने ट्रेन उपलब्ध न कराने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। रेलवे ने लिखा कि अभी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी, दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ रूट्स पर बसें जा सकती हैं, लेकिन रामेश्वरम के रूट पर बस जाने में दिक्कत है। रामेश्वरम की ही सबसे ज्यादा मांग है। आज भी ट्रेन जानी थी और अगले दिन भी जानी है। इसलिए उन लोगों तक मीडिया के माध्यम से शीघ्र सूचना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

सबसे अधिक रामेश्वरम जा रहे यात्री

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सबसे ज्यादा रामेश्वरम यात्रा पर यात्री गए हैं। सबसे ज्यादा मांग रामेश्वरम की ही है। अभी तक दिल्ली से रामेश्वरम की यात्रा पर करीब 8 हज़ार यात्री जा चुके हैं और 12963 यात्रियों की लिस्ट अभी लंबित है। सबसे ज्यादा 12 ट्रेन रामेश्वरम की ही हैं, जिसमे एक हज़ार से अधिक यात्री जाने वाले हैं। द्वारकाधीश दूसरा सबसे पॉपुलर स्थान है। इसके बाद जगन्नाथपुरी, शिरडी, अजमेर व वैष्णोदेवी के रूट्स पर काफी मांग है। जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर सूचित किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र ने बताया भारत समेत एशिया में 50 करोड़ लोग अब भी हैं कुपोषण के शिकार

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों द्वारा बुधवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत में लगभग 50 करोड़ लोग अब भी कुपोषण के शिकार हैं और 2030 तक भुखमरी को मिटाने के लिए हर महीने खाद्य असुरक्षा से लाखों लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है।

विश्व निकाय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कुपोषण के चलते उम्र और लंबाई के हिसाब से बच्चों में कम वजन और बौनेपन तथा अन्य समस्याओं से निपटने जैसे क्षेत्रों में प्रगति की गति धीमी है और कई मामलों में तो यह पीछे की तरफ चली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असमानता की खराब होती स्थिति का मतलब यह है कि क्षेत्र में अपेक्षाकृत तेज आर्थिक वृद्धि और आय लाखों लोगों के लिए पर्याप्त और पोषक आहार सुनिश्चित करने में मदद के वास्ते पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है तथा लाखों लोग अब भी गरीबी में जी रहे हैं। रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि सरकारों को गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नीतियों से जोडना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों में भुखमरी के खात्मे और सभी लोगों के लिए वर्षभर पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन में क्षेत्रीय प्रतिनिधि कुंधावी कादिरेसन ने कहा, हम सही रास्ते पर नहीं हैं। अल्पपोषण में कमी लाने के कार्य में पिछले कई वर्षों में प्रगति धीमी देखी गई है। इसमें कहा गया है कि एशिया प्रशांत में कुल आबादी का पांचवें से अधिक हिस्सा हल्की से लेकर गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में अल्पपोषित 47.9 करोड़ लोगों में आधे से ज्यादा दक्षिण एशिया में रहते हैं।

दिल्ली की हवा अभी बेहद खराब, बारिश बढ़ाएगी ठंड

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। इसके अलावा स्मॉग का कहर भी दिल्ली वालों पर टूटने लगा है। बुधवार सुबह एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 392 पर पहुंच चुका था, तो साथ ही कई इलाकों में सुबह स्मॉग की मोटी चादर भी नजर आई। हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों में इंडेक्स 400 से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान के 22 डिग्री पर जाने की संभावना है। मौसम विभाग घोषणा कर चुका है कल और परसों दोपहर के बाद राजधानी में तेज आंधी के साथ ओलों की बरसात भी हो सकती है। फिलहाल देखना यह है कि उसकी यह भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। मौसम विभाग यह भी कह रहा है कि आगामी दिनों में तापमान में लगातार गिरावट आती रहेगी। अगले सप्ताह जबर्दस्त ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी।

दूसरी ओर प्रदूषण से जुड़ी सरकारी एजेंसियों ने आज जानकारी दी कि सुबह एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 392 पर पहुंच चुका था। लेकिन हालात और ज्यादा खराब हैं।

उसका कारण यह है कि राजधानी में प्रदूषण से जुड़े 37 निगरानी केंद्रों पर सुबह 18 में प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर चल रहा था। एजेंसियों का कहना है कि शाम को पूरी दिल्ली में इसका स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी में आ सकता है काईमेट का कहना है कि दिल्ली का वायु प्रदूषण खराब से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में चलने वाली हवाएं बहुत हल्की हैं। जबकि दिल्ली और एनसीआर के कुछ स्थान खराब श्रेणी में देखे जा रहे है। स्काइमेट विशेषज्ञों के अनुसार, 12 दिसंबर तक हल्की बारिश की गतिविधियों की उम्मीद है जो वायु प्रदूषकों को फैलाने में मदद करेगी। ऐसा हुआ तो प्रदूषण कम हो जाएगा।

नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में RSS चलाएगा देशव्यापी अभियान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में वह देशभर में अभियान चलायेगा जिससे डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित होने वाले है और इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति (रू) और अनुसूचित जनजाति (स्त्र) के लोग हैं। असम में विधेयक का सीमित प्रभाव होने का तर्क देते हुए आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दावा किया कि राज्य में इससे केवल छह लाख लोगों को लाभ मिलेगा, वहीं पश्चिम बंगाल में 72 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक दशक से रहने वाले प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को लाभ मिलेगा और वे देश के 'स्वाभाविक नागरिक' हैं। पड़ोसी देशों में हिंदू, सिख, जैन और अन्य समुदाय को प्रताड़ित किये जाने के लिए विभाजन को जिम्मेदार ठहराते हुए संघ पदाधिकारी ने कहा कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के कारण ही यह हुआ।

1.50 करोड़ लोगों को होगा लाभ

संघ के सूत्रों ने कहा, ''वे हमारे ही लोग हैं और इससे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ होगा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं जिन्हें नागरिकता मिलेगी और आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।'' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाकर पंचायत स्तर तक पहुंचा जाएगा और लोगों को इस विधेयक के लाभ के बारे में जागरुक किया जाएगा। विधेयक में नागरिकता देने के लिए धर्म का मानदंड रखने के पीछे का तर्क पेश करते हुए संघ पदाधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का राज्य धर्म इस्लाम है और मुस्लिम वहां के 'प्रिय नागरिक' हैं। हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों के लोगों को उनके धर्म के कारण इन देशों में यातनाएं दी जाती हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं।

RISAT-2BR1 अंतरिक्ष से रखेगा भारत की सुरक्षा पर नजर

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। भारतीय सुरक्षा के लिहाज से इसरो द्वारा रीसैट2बीआरा1 को लॉच करना बेहत खास बात है। 11 दिसंबर यानी आज 3 बजकर 25 मिनट पर ताकतवर राडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट2बीआर1 की सफल लॉन्चिंग कर दी गई है। इस उपग्रह की खुबियों के कारण ही इसे खुफिया उपग्रह कहा जा रहा है। इस उपग्रह की एक नहीं कई खासियत है। इसरो की ओर से रीसैट2बीआरा सैटेलाइट के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के बाद भारत की राडार इमेजिंग ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये उपग्रह 628 किलोग्राम वजनी है इसको पृथ्वी की कक्षा से 576 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस उपग्रह के स्थापित होने के बाद से ही ये काम करना शुरू कर देगा और कुछ देर बाद ही इससे तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस

उपग्रह के स्थापित होने से भारतीय सीमाओं की निगरानी करना और उनकी सुरक्षा को बनाने की प्लानिंग का काम भी बेहद मजबूती से किया जा सकेगा। बता दें कि इस उपग्रह से किसी भी मौसम में साफ चित्र ले सकते हैं। अगर किसी दिन घने बादल रहे और बारिश होने की संभावना हुई ऐसे में भी इस उपग्रह से एकदम साफ तस्वीर ली जा सकती है और इससे दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने में मदद मिलेगी। इसरो द्वारा बनाई गई इस सैटेलाइट से कृषि, जंगल और आपदाओं के दौरान भी भरपूर मदद मिल सकेगी। रीसैट2 सैटेलाइट को भारत में 26/11 मुंबई हमले के बाद लॉच किया था। इस सैटेलाइट ने खास तौर पर समुद्री सीमाओं पर काफी सराहनीय काम किया है। सीमाओं की फास्ट ट्रैक मॉनिटरिंग करना संभव हो पाया था। रीसैट 2बीआर1 में लगने वाले डिफेंस इंटेलिजेंस सेंसर को भारत में ही बनाया गया है। इसमें मौजूद एक्स बैंड एसएआर कैपेबिलिटी की बजह से ही ये उपग्रह घने से घने अंधेरे में और हर मौसम में साफ तस्वीरे ले सकेगा। इस सैटेलाइट से किसी खास इलाके में किसी खास जगह की साफ तस्वीर ली जा सकती है। इसमें क्षमता है कि ये करीब सौ किमी करे इलाके की तस्वीर लेकर जमीन पर भेजेगा जहां पर इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जा सकेगा। इसकी तैनाती खासतौर पर सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है।

विभाजन के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग जिम्मेदार

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। राज्य सभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस आरोप को बेबुनियाद बताया कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है बल्कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग ने दिया था और इसमें ब्रिटिश सरकार की भी भूमिका थी।

शर्मा ने सदन में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किये गये इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हम इस विधेयक का केवल राजनीतिक रूप से नहीं कर रहे है बल्कि इसलिए इसके खिलाफ हैं क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के न केवल विरुद्ध है बल्कि यह उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला

है और यह भारतीय गणतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि 1937 में अहमदाबाद में हिन्दू महासभा के सम्मेलन में द्विराष्ट्र का सिद्धांत पहली बार पेश किया गया था जिसकी अध्यक्षता वीर सावरकर ने की थी। इसके बाद 1938 में मुस्लिम लीग की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। विभाजन के पीछे अंग्रेजों की भी भूमिका थी। शाह इन बातों का उल्लेख क्यों नहीं करते। वह विभाजन का दोष कांग्रेस पर क्यों लगाते हैं, यह गलत है। उन्होंने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था और इस पर व्यापक चर्चा की गयी थी, इसके बाद ही संविधान में इससे संबंधित प्रावधान किये थे। उन्होंने नागरिकता के मामले में धर्म को आधार नहीं बनाया था और क्या वह समझदार नहीं थे।

अयोध्या प्रकरण में पुर्निवचार याचिकाओं पर आज विचार करेगा कोर्ट

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राम जन्मभूमिबाबरी मस्जिद भूमि विवाद में नौ नवंबर के फैसले पर पुर्निवचार के लिये दायर याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को चैंबर में विचार करेगा। शीर्ष अदालत के इस फैसले ने अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इन पुर्निवचार याचिकाओं पर चैंबर में विचार करेगी। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं। अयोध्या प्रकरण में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से

अपना फैसला सुनाया था।

चूंकि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके स्थान पर संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शामिल किया गया है। विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के नौ नवंबर के फैसले पर पुर्निवचार के लिये याचिकाएं छह दिसंबर को मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने दायर की थीं।

इन सभी पुर्निवचार याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन प्राप्त है। इससे पहले दो दिसंबर को पहली पुर्निवचार याचिका मूल वादी एम सिद्दिक के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अशहद राशिदी ने दायर की थी। संविधान पीठ के इस फैसले पर पुर्निवचार के लिये अब तक 40 से अधिक याचिकायें दायर हो चुकी हैं।

पुर्निवचार याचिका दायर करने वालों में इतिहासकार इरफान हबीब, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रभात पटनायक, मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर, नंदिनी सुंदर और जॉन दयाल शामिल हैं।

इनके अलावा हिन्दू महासभा ने भी न्यायालय में पुर्निवचार याचिका दायर करके मस्जिद निर्माण के लिये पांच एकड़ भूमि उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को आबंटित करने के निर्देश पर सवाल उठाये हैं। विदित हो कि 14 मार्च, 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ मूल मुकदमे के पक्षकारों को ही मामले में अपनी दलीलें पेश करने की इजाजत होगी। पीठ ने इस मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को हस्तक्षेप करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इस प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने नौ नंवबर को अपने फैसले में समूची 2.77 एकड़ विवादित भूमि राम लला' विराजमान को दे दी थी और केंद्र को निर्देश दिया था कि वह अयोध्या में एक मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करे।

दिल्ली अग्निकांड में दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की: मनोज तिवारी

नई दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में भीषण अग्निकांड का मामला आज फिर लोकसभा में गूंजा। बीजेपी सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस मुद्दा को उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिये।

हालांकि इससे पहले सोमवार को भी यह मुद्दा उठा था। तिवारी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अवैध ढंग से फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने इस आरोप को खारिज कर दिया।वहीं सांसद चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिये और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिये। उन्होंने मांग कि पीड़ित परिवारों को 2525 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मालूम

हो कि राजधानी के फिल्मिस्तान इलाके में हाल ही में फैली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई जिसमें 43 लोगों की जान चली गई। जबकि अभीभी गंभीर हालात में अस्पताल में कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने बिल्डिंग मालिक के भाई को हिरासत में ले लिया है।

महिला हेल्पलाईन न.

डीएमआरसी–155370
सीआईएसएफ–22185555
दिल्ली पुलिस–1091
दिल्ली सरकार–181
कहीं भी–कभी भी–1090

समाचार एजेंसी
वेब वार्ता
पल-पल की खबर हर पल
समाचार एजेंसी का सदस्य बनने के लिए संपर्क करें
9650061234

एक नजर

सैमसंग ने आईआईटी गुवाहाटी में शुरू किया सैमसंग डिजिटल अकादमी

नयी दिल्ली। स्मार्टफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली कंपनी सैमसंग इंडिया ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी में सैमसंग डिजिटल अकादमी का बुधवार को उद्घाटन किया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत सैमसंग इनोवेशन लैब में आईआईटी गुवाहाटी के विद्यार्थियों को इंटरनेट ऑफ ड्क्षथग्स (आईओटी), एम्बेसडेड सिस्टमम्स, कृत्रिम मेधा और मशीन लिर्निंग का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे उन्हें उद्योग संबंधी कौशल सीखने और रोजगार के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। कंपनी का लक्ष्य इस अकादमी में अगले तीन साल में 300 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की है। बयान के अनुसार इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोणोवाल ने कहा कि आईआईटीगुवाहाटी में सैमसंग डिजिटल अकादमी कार्यक्रम से राज्य को असम को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी प्रणालियों के विकास में भूमिका निभाने में मदद मिलेगी तथा राज्य में स्थायी रोजगार के विकल्प विकसित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक किहो किम ने कहा, ÷सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उन्नत एवं उभरती तकनीकों पर संयुक्त शिक्षण, परामर्श और अनुसंधान प्रोत्साहन में सहयोग के लिए पिछले कई वर्षों से भारत के शीर्ष इंजीनियड्क्षरग संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इंटेल ने छोटे, मध्यम उपक्रमों के बीच प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये शुरू की मुहिम

नई दिल्ली। प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के साथ मिलकर छोटे एवं मध्यम उपक्रमों के बीच प्रौद्योगिकी इस्तेमाल बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रव्यापी मुहिम की शुरुआत की है। भारत एसएमई फोरम ने इसकी जानकारी दी है।फोरम के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 19 राज्यों के 1,29,537 एमएसएमई में से 34 प्रतिशत से अधिक ने बताया कि वे कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं से संवाद के लिये डिजिटल माध्यमों को अपना रही हैं। हालांकि, इनमें से महज सात प्रतिशत ने ही पूरी तरह से डिजिटल माध्यम को अपनाया है। सर्वेक्षण के अनुसार, प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने की निम्न दर का कारण कारोबारी फायदे के बारे में समझ व सलाह का अभाव, प्रौद्योगिकी अपनाने में होने वाले निवेश की लागत का वहन करने में आनाकानी तथा प्रौद्योगिकी का प्रबंधन करने में सक्षम श्रमबल का अभाव है। एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव अल्का अरोड़ा ने देश के करीब छह करोड़ एमएसएमई के विकास के लिये प्रौद्योगिकी की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ''इनमें से अधिकांश सूक्ष्म श्रेणी में हैं तथा कुछ छोटे एवं मध्यम श्रेणी में हैं ।

अकाली दल को स्थापना नहीं शर्म दिवस मनाना चाहिए: तरविंदर

दिल्ली कमेटी के गुरुद्वारों परिसरों में महिलाएँ सुरक्षित नहीं

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली । शिरोमणी अकाली दल का स्थापना दिवस मनाने का अधिकार बादल दल को नहीं है, बल्कि बादल दल को अकाली दल की स्थापना के मूल उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए शर्म दिवस मनाना चाहिए। उक्त विचार इंटरनेशनल सिख कौंसिल की अध्यक्ष बीबी तरविंदर कौर खालसा तथा उपाध्यक्ष जगजीत सिंह मूंदड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। खालसा ने कहा कि 14 दिसम्बर 2019 को सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल के द्वारा दल का 99वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1920 में अकाली दल की स्थापना सिख कौम की परंपराओं की रक्षा करने के लिए

हुई थी। पर आज अकाली दल अपने आपको पंजाबी पार्टी बताने में गर्व महसूस करता है। अकाली दल ने धर्म पर सियासत को इतना हावी कर दिया है कि अब शिरोमणी और दिल्ली कमेटी पर सियासी लोग आकर बैठ गए है। जिस वजह से सिख सिद्धांतों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। खालसा ने दावा किया कि हमारे बुजुर्गों ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर काबिज महंत नारायणु की सोच को हटाने के लिए अकाली दल की स्थापना की थी,पर आज अकाली दल उसी नारायणु सोच पर चल रहा है। खालसा ने दावा किया कि आज दिल्ली कमेटी के प्रबंधकों की नाक के नीचे गुरुद्वारा परिसरों में महिलाएँ सुरक्षित नहीं है। नगर कीर्तन में सिख पूजा पद्धति के उलट मूर्तियों की झाँकी निकाली जा रहीं है। सिख कौम की महान विरासत अदालतों के आदेश पर तबाह हो रही है, पर कमेटी प्रबंधकों को सिर्फ विधायक बनने की चिंता है। खालसा ने बताया कि गुरुद्वारा माता सुंदरी और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब परिसर में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक लड़की को कथित तौर पर जबरदस्ती दबोचने की बात सामने आई है। आरके पुरम 9 सेक्टर के गुरुद्वारे में कमेटी स्टाफ कथित देह व्यापार करवा रहा था। हमारी जानकारी अनुसार पकड़े गए आरोपी सेवादार ने भी अपने लिखित ब्यान में इस बात को कबूल किया है। आज महंत नारायणु की तर्ज पर औरतों का कथित उत्पीड़न और सिख सिद्धांतों की अनदेखी दिल्ली के गुरुद्वारों में आम बात हो गई है। कमेटी सदस्य परमजीत सिंह चंडोक शराब के ठेके से बीयर खरीदते कैमरे में कैद हो चुके है। फिर क्यों न कहा जाए कि शराब और शबाब का सेवन करने वाले अकाली नहीं हो सकते। इसलिए इन्हें स्थापना दिवस मनाने की जगह शर्म दिवस मनाना चाहिए।

जबरन देह व्यापार में धकेली गई तीन किशोरी बरामद, 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली /कोलकाता। विधाननगर कमिशनरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर जबरन देह व्यापार में धकेली गई तीन किशोरियों को न्यूटाउन के रिहायसी इलाके से बरामद किया है। 16 साल की लड़कियों को पिछले कई महीनों से वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें बरामद करने में अंतरराष्ट्रीय न्याय मिशन (आइजेएम) ने मदद की।

वहीं, किशोरियों से जबरन देह व्यापार कराने के आरोप में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम सुपर्णा मंडल (42), अभिजीत मंडल (37) और पायल हीरा (19) है। तीनों मिल कर न्यूटाउन में दो कमरों के अपार्टमेंट में तस्करी का रैकेट चला रहे थे। पुलिस की मानें तो मुख्य आरोपित सुपर्णा मंडल है, जो पूर्व यौनकर्मी है। सुपर्णा ही ग्राहकों से सौदेबाजी और नाबालिग लड़कियों का शोषण करने के लिए अपने किराए के घर का इस्तेमाल करती थी। आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) 366ए, 370, 370ए, 372 और 373 के तहत मामला दर्ज किया गया, जो कि नाबालिग लड़कियों की खरीद, तस्करी, तस्करी करने वाले व्यक्तियों का शोषण व नाबालिगों की बिक्री के उद्देश्य से एकत्र करने की धारा के तहत है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बरामद लड़कियों में से एक कक्षा आठ तक पढ़ी है। पर उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। जब वह छोटी थी तब उसके माता पिता अलग हो गए थे। वह अपने दादा दादी के साथ रह रही थी।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक पेश

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नयी दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को मातापिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्यण संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर छह माह तक कारावास या 10 हजार रूपये जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने निचने सदन में उक्त विधेयक पेश किया।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि इससे संबंधित अधिनियम पर विचार करने के बाद सचिवों के समूह ने एक समान आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सभी फायदा देने, वरिष्ठ नागरिकों के लिये भरण पोषण की रकम में वृद्धि करने और गृह देखरेख सेवाओं के मानकीकरण की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत पुत्रवधू और दामाद को बालक की परिभाषा की परिधि में लाने की बात भी कही गई है। इसका मकसद मातापिता और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भरण पोषण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने में वृद्धि करना, अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आवेदनों सहित भरण पोषण आवेदनों का शीघ्र निपटान का उपबंध करना है। इसमें मासिक भरण

पोषण की 10 हजार रूपये की ऊपरी सीमा को हटाने की बात कही गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिये विशेष पुलिस यूनिट का गठन करने तथा प्रत्येक थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिये शीर्ष अधिकारी नियुक्त करने तथा वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन रखने की बात कही गई है। विधेयक में दुर्व्यवहार के रूप में शरीरिक रूप से दुर्व्यवहार, गाली गलौच करना, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार, अनदेखी करना और परित्याग, हमला करना, चोट पहुंचाना, शरीरिक एवं मानसिक रूप से कष्ट देना शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये एक हेल्प लाइप स्थापित करेगी जिसका पूरे देश में एक समान नंबर होगा तथा जिसे स्वास्थ्य देखरेख, पुलिस विभाग और संबद्ध अभिकरणों से जोड़ा जायेगा। इसमें कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी अस्पताल चाहे, वे सरकार द्वारा पूर्णत- या अंशतः वित्त पोषित हों या निजी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख संस्थाएं हों, वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव विस्तर प्रदान करती है। सरकार या कोई संगठन, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो किसी भौतिक या मानसिक दुर्बलता के कारण दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करने में कठिनाई महसूस करते हैं तो उनके गृह पर देखरेख सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा। विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों के लिये प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ।

अधिवक्ताओं ने की नेशनल हाईवे पर टोल फ्री पास जारी करने की मांग

गाजियाबाद । कलेक्ट्रेट कम्पाउंड में बने 34 अधिवक्ता चैम्बर्स पर स्ववित्त पोषित आधार पर दो मंजिला चैम्बर्स बनाने के लिए अनुमति दिलाने व नेशनल हाईवे पर आवागमन के लिए ट्रोल फ्री पास जारी करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माधयम से प्रमुख सचिव राष्ट्रीय राज्य मार्ग को ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन में कहा गया कि जनपद न्यायालय व जिला कलेक्ट्रेट कम्पाउंड में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्तागण के लिए चैम्बर्स बिल्डिंग विस्तार के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है तथा प्रत्येक वर्ष लगभग 100150 अधिवक्ता इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तथा उनके लिए चैम्बर्स की व्यवस्था वर्तमान में बने चैम्बर्स के ऊपर दो मंजिला चैम्बर्स बनाकर की जा सकती है। कलेक्ट्रेट कम्पाउंड में 34 अधिवक्ता चैम्बर्स के ऊपर दो मंजिला चैम्बर स्ववित्त पोषत आधार पर बनाने के लिए अधिवक्ता तैयार है किंतु उक्त राजस्व विभाग की संपत्ति पर बने होने के कारण संबंधित राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

हैदराबाद मुठभेड़ की जांच के लिये पूर्व न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करेगा अदालत

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह तेलंगाना में पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस घटना का संज्ञान लिया है।'' पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिर्फ यही चाहती है कि उच्चतम न्यायालय के दिल्ली में रहने वाले किसी पूर्व न्यायाधीश को इस मामले की जांच करनी चाहिए। पीठ ने कहा, हमारा प्रस्ताव शीर्ष अदालत के किसी पूर्व न्यायाधीश को इस मामले की जांच के लिये नियुक्त करने का है।''

पीठ ने स्पष्ट किया कि इस घटना की जांच करने वाले पूर्व न्यायाधीश को दिल्ली में रहकर काम करना होगा। पीठ ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश से इस घटना की जांच करने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। न्यायालय ने इस मुठभेड़ की विशेष जांच दल से स्वतंत्र जांच कराने के

लिये दायर जनहित याचिकाओं को बृहस्पतिवार के लिये सूचीबद्ध करते हुये संबंधित पक्षकारों के वकीलों से कहा कि वे नियुक्ति के लिये पूर्व न्यायाधीशों के नामों के बारे में सुझाव दें। तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता कृष्ण कुमार ड्क्षसह ने कहा कि उन्होंने मुठभेड़ के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित निर्देशों का पालन किया है और सारे मामले को पहले ही राज्य सीआईडी के सुपुर्द कर दिया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने के लिये शीर्ष अदालत में दो याचिकायें दायर की गयी हैं। पहली याचिका अधिवक्ता जी एस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने दायर की है जबकि दूसरी याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। मणि और यादव की जनहित याचिका में दावा किया गया है कथित मुठभेड़ फर्जी' है और इस घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दायर की जानी चाहिए। तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि ये आरोपी पुलिस के साथ हुई फायड्क्षरग में मारे गये। यह घटना सवेरे करीब साढ़े छह बजे हुयी जब जांच की प्रक्रिया के दौरान उन्हें वारदात की पुनर्रचना के लिये घटनास्थल पर ले जाया गया था। इन चारों आरोपियों को हैदराबाद के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग44 पर गोली मारी गयी थी, जहां 27 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का जला हुआ शव मिला था।

जेएनयू के अधिकारियों को पुलिस दे सुरक्षा : अदालत

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस को जेएनयू के कुलपति, रजिस्ट्रार सहित प्रशासनिक कर्मचारियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने को कहा ताकि वे मुख्य कार्यालय में घुस सकें, जिसे प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बाधित कर रखा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम ड्क्षसह ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश तब जारी किया जब अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार छात्रों के प्रदर्शन के कारण प्रशासनिक खंड में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अदालत को स्थिति के बारे में बताया गया। इससे पहले अदालत ने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने दो प्रोफेसरों की संलिप्तता वाले यौन उत्पीडन् के मामले में अब तक अपना जवाब क्यों नहीं दाखिल किया है । विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में सुबह में बताया गया तो अदालत ने केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा और दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (फौजदारी) राहुल मेहरा को भोजन अवकाश के बाद की सुनवाई में पेश होने को कहा। भोजन अवकाश के बाद की सुनवाई के दौरान अरोड़ा ने अदालत को बताया कि अगस्त 2017 में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि छात्र प्रशासनिक खंड से 100 मीटर दूर रहकर प्रदर्शन करें और इमारत में नहीं घुसें। उन्होंने अदालत को बताया कि छात्रों द्वारा आदेश नहीं माने जाने पर पुलिस से दखल देने को भी कहा गया था । दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सुरक्षा और सहयोग प्रदान करने को कहा ताकि वे प्रशासनिक खंड में प्रवेश कर पाएं और अपना काम शुरू कर सकें।

कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन विधेयक को बताया विभाजनकारी, संविधान विरूद्ध

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) में धार्मिक आधार पर नागरिकता देने के प्रावधानों को ''विभाजनकारी'' करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को इस विधेयक को संविधान के विरुद्ध करार दिया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुये उच्च सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार की यह दलील तर्कसंगत नहीं है कि पिछले 70 सालों में अन्य देशों से भारत आने वाले प्रताड़ित लोगों को नागरिकता नहीं दी गयी। शर्मा ने कहा कि इससे पहले पड़ोसी देशों से ही नहीं बल्कि श्रीलंका, केन्या और युगांडा सहित अन्य देशों से भी भारत आने वाले शरणार्थियों को शरण दी गयी। इसके लिये नागरिकता कानून में नौ बार संशोधन किया गया लेकिन एक बार भी धार्मिक आधार पर नागरिकता नहीं दी गयी। उन्होंने कहा, ''भारतीय संविधान धार्मिक आधार पर भेदभाव का स्पष्ट निषेध करता है।

संविधान की इस मूल भावना का पालन करते हुये मानवीय आधार पर नागरिकता दी गयी। इसलिये हम धार्मिक आधार पर नागरिकता देने को संविधान के विरूद्ध मानते हुये इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।'' शर्मा ने लोकसभा में इस विधेयक पर जवाब के दौरान गृह मंत्री द्वारा धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के लिये कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराने को गलत बताते हुये कहा, ''1943 में सावरकर जी ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी कि मुझे जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रस्ताव से कोई आपत्ति नहीं है।'' उन्होंने इसके लिये कांग्रेस को दोष दिये जाने को गलत बताया।शर्मा ने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुये पूछा कि आखिर देश के विभाजन में अंग्रेजों की भूमिका का जिक्र क्यों नहीं किया जाता है। कांग्रेस नेता ने विधेयक को भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा होने के कारण इसे लागू करने की प्रतिबद्धता को 'राजहठ' करार देते हुये कहा, ''किसी दल का घोषणापत्र संविधान से नहीं टकरा सकता है, ना उसके ऊपर जा सकता है।

उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर 2000 शौचालय बनेंगे: गोयल

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर के रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई एवं शौचालय समेत अन्य सुविधाओं में वृद्धि का दावा करते हुए आज कहा कि अब शहरी उपनगरीय स्टेशनों पर दो हजार शौचालय बनाये जाएंगे। गोयल ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के निरंतर प्रयास से रेलवे स्टेशनों में साफ सफाई अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि उप शहरी इलाकों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण शौचालय की व्यवस्था उतनी नहीं हो पायी है जितनी जरूत है लेकिन जल्द ही उप शहरी इलाकों के रेलवे स्टेशनों पर करीब दो हजार शौचालय बनाये जाएंगे।

गोयल ने कहा कि रेलवे ने 90 फीसदी शौचालयों को बायो टॉयलेट में तब्दील कर दिया। इससे रेलवे ट्रैकों पर हाथों से गंदगी साफ करने को समाप्त किया जा रहा है।द्रमुक के दयानिधि मारन तथा एमके कनिमोझी ने प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी की महत्वाकांक्षी योजना खुले में शौच से मुक्ति की अपार सफलता के बाद भी रेल तथा रेलवे स्टेशनों पर इसकी झलक नहीं दिखायी दी जाती है। इन सदस्यों ने कहा कि वह पहले भी रेल मंत्री के समक्ष स्टेशनों की स्वच्छता को लेकर सवाल किये थे लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिले थे।

दिल्ली पुलिस से संतुष्ट नहीं राजधानी के 72 फीसद लोग, सर्वे में हुआ खुलासा

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है। बात चाहे अपराध के शिकार होने वाले लोगों की हो या फिर अपराध के प्रत्यक्षदर्शियों की, सभी पुलिस से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। यही नहीं लोग अपराध की सूचनाएं देने से भी कतराते हैं। यह बात एक सर्वे में सामने आई है। इसमें राजधानी दिल्ली के 72 फीसद लोग पुलिस से असंतुष्ट थे। प्रजा फाउंडेशन ने हंसा रिसर्च के साथ मिलकर राजधानी में किए गए सर्वे किया है। इसमें पुलिस व कानून व्यवस्था की स्थिति पर लोगों की राय ली गई। प्रजा फाउंडेशन के निदेशक मिलिंद म्हस्के ने बताया कि दिल्ली में रहने वाले 27 हजार 121 परिवारों को सर्वे में शामिल किया गया। इसमें से दस प्रतिशत ने अपराध होते हुए देखा था, लेकिन इसमें 57 फीसद ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी, जबकि 35 फीसद ने अपराध का सामना किया और 26 फीसद ने पुलिस को मामले की जानकारी ही नहीं दी। अपराध होते देखने वाले सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही पुलिस थाने में जाकर एफआइआर दर्ज कराई, जबकि अपराध का सामना करने वाले पांच प्रतिशत लोगों ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाले 72 फीसद लोग पुलिस की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। अपराध का सामना करने वाले और प्रत्यक्षदर्शियों में से 26 फीसद लोगों ने इसलिए पुलिस को सूचना नहीं दी, क्योंकि उन्हें पुलिस और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है।

रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरटीआइ के जरिये ली गई जानकारी में पता लगा कि राजधानी में दुष्कर्म के मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए मामलों में से 63 फीसद पीड़ित मासूम बच्चे थे। दुष्कर्म के दर्ज कुल 1965 मामलों में 1237 में दंरदों ने मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं, वर्ष 201819 में अपहरण कर और बहलाफुसलाकर भगाने के मामलों में 94 प्रतिशत मामले बच्चों के अपहरण के थे। इनकी संख्या 5555 थी। इनमें से 70 फीसद मामलों में पीड़ित लड़की थी। आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 201415 से वर्ष 2018 19 की अवधि में दिल्ली में दर्ज किए गए दुष्कर्म के मामलों में छह प्रतिशत की कमी आई है। जबकि, छेड़छाड़ की घटनाओं में 30 फीसद की कमी आई है।

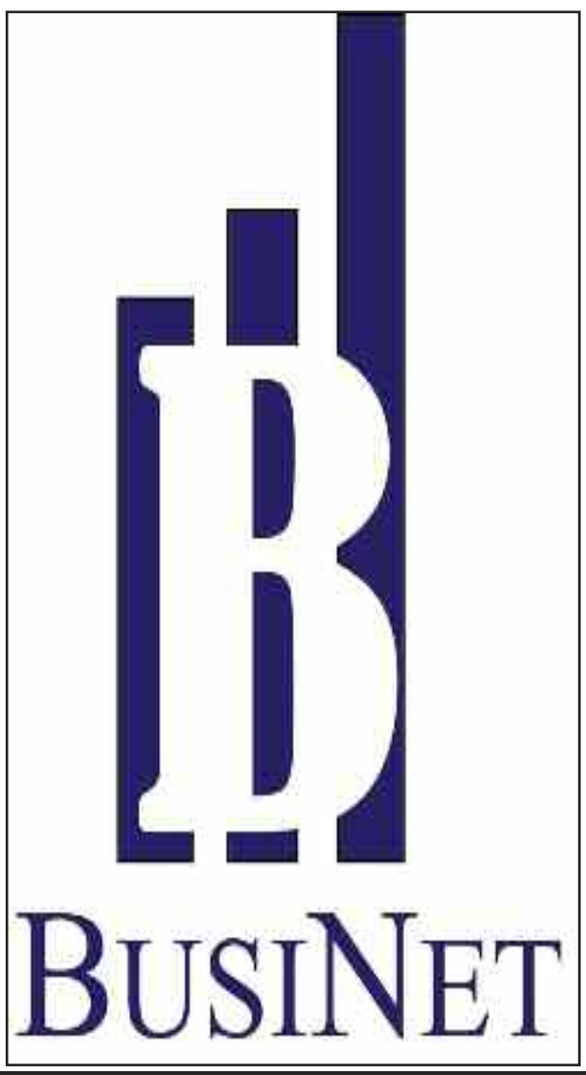

संपादकीय

महिलाओं के मुद्दे पर भाजपा को घेर रहीं प्रियंका जरा राहुल के बयानों को तो देख लें

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का दो दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा काफी धमाकेदार रहा। अपने दौरे के दौरान एक तरफ उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली भारत बचाओ रैली में भीड़ जुटाने के लिए यूपी कांग्रेस के नेताओं के पेंच कसे तो दूसरी तरफ उन्नाव में रेप और जलाकर मार देने की घटना पर सियासत भी की। 17 जुलाई 2019 को सोनभद्र में हुए नरसंहार के समय वहां जाकर जिस तरह से प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा था, वैसा ही आक्रोश प्रियंका ने उन्नाव रेप पीड़िता को जलाकर मार देने के मामले में दिखाया। कांग्रेसियों ने सोनभद्र नरसंहार की घटना की तरह उन्नाव में रेप की घटना को लेकर उन्नाव से लेकर लखनऊ तक खूब बवाल मचाया, लेकिन इस बार योगी सरकार ने सोनभद्र जाती प्रियंका को मिर्जापुर में रोक देने जैसी गलती नहीं की। दोनों ही मौके पर योगी सरकार ही नहीं समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी भी बैकफुट पर नजर आईं। यही वजह थी, जैसे ही प्रियंका के उन्नाव जाने की खबर भाजपा, सपा और बसपा को लगी तो योगी सरकार ने अपने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को रेप पीड़िता से मिलने के लिए रवाना कर दिया। उनके साथ उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज भी मौजूद थे। उधर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए विधान भवन के बाहर धरने पर बैठ गए, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती महिला उत्पीड़न और रेप की शिकायत को लेकर राज्यपाल आनंदी बेन के पास ज्ञापन लेकर पहुंच गईं, लेकिन सभी दलों के दिग्गज प्रियंका की सियासी तेजी के सामने बौने नजर आए। खैर, बात प्रियंका की कि जाए तो उन्नाव रेप पीड़िता को जलाने के मामले की घटना में प्रियंका ने यह ध्यान भी रखा कि सोनभद्र जैसी चूक अबकी न हो। इसीलिए उन्होंने उन्नाव में लड़की के साथ रेप और जलाकर मार देने की घटना के पीछे जिस प्रधान का नाम सामने आ रहा था, उसे भाजपा का करीबी बताने में देरी नहीं की। गौरतलब है कि सोनभद्र नरसंहार में जिस प्रधान का नाम आरोपी के रूप में सामने आया था, उसे भाजपा ने कांग्रेसी बताकर प्रियंका और कांग्रेस की काफी घेराबंदी की थी। कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़िता को जलाकर मार देने की सनसनीखेज वारदात पर सियासत करने के लिए एक साथ दो मोर्चे खोले। उन्नाव जाकर प्रियंका रेप पीड़िता के परिवार से मिलीं तो लखनऊ में कांग्रेसी, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के गेट पर धरना देकर बैठ गए, जिन्हें चार घंटे की मशक्कत और लाठीचार्ज के बाद बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हटाया जा सका। बहरहाल, कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा की तेजी को राजनैतिक पंडित 2022 के विधान सभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते तीन दशक से नाकामयाबी का स्वाद चख रही कांग्रेस को 2022 के विधान सभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव के समय प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कहा भी था कि हमारा लक्ष्य 2022 के विधान सभा चुनाव हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जनता से जुड़े मुद्दों कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, बढ़ती महंगाई और बिजली दरों में बढ़ोत्तरी को जोर शोर से उठाने का फैसला लिया है। इसीलिए तो बिजली का दाम बढ़ता है तो प्रियंका सबसे पहले ट्वीट करती हैं। किसान आत्महत्या करता है तो प्रियंका तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। इसी तरह प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कांग्रेसी गले में प्याज की माला पहन कर घूमते दिखने लगते हैं। महिलाओं पर अत्याचार का मामला आता है तो प्रियंका स्वयं मैदान में कूद पड़ती हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस अब जनता को ही सरकार के खिलाफ खड़ा करके अपनी सियासी जमीन बनाने की तैयारी में है। दो दिन तक प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने नेताओं से दो टूक कह दिया कि वे जनता के मुद्दों पर उनके साथ हमेशा खड़े हों।

महिला हेल्पाइन

डीएमआरसी	155370
सीआईएसएफ	22185555
दिल्ली पुलिस	1091
दिल्ली सरकार	181
कहीं भी कभी भी	1090

हिंदी दैनिक वूमेन एक्सप्रेस

खबर एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें
चेम्बर नंबर-302, वधवा बिजनेस सेंटर, डी-288-89/10,
नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टैशन गेट नंबर -1,
विकास मार्ग, नई दिल्ली - 110092
मोबाइल : 07042999974/ 09013518518
प्रधान संपादक : खुशबू पाण्डेय
प्रबंध संपादक : विनोद मिश्रा
राजनीतिक संपादक : मनोज श्रीवास्तव
विज्ञापन प्रबंधक : रिजवाना नसीम
कानूनी सलाहकार : सत्य प्रकाश
www.womenexpress.in
Email : thewomenexpress@gmail.com

इंदौर कार्यालय

102 , राजानी भवन , हाई कोर्ट के सामने,एम् ,जी रोड , इंदौर (मध्यप्रदेश)
रजनी खेतान (ब्यूरो चीफ)
मोबाइल : 08770587699, 09826024018

इलाहाबाद कार्यालय

17/33, महात्मा गांधी मार्ग
(माया बाजार) सिविल लाइनस।
फोन : 05322560285
09415215390
प्रबंध संपादक : विनोद मिश्रा

संविधान के अनुरूप समस्याओं का समाधान

(डॉ दिलीप अग्निहोत्री)

नरेंद्र मोदी सरकार ने दशकों से लंबित संवेदनशील समस्याओं के समाधान का संकल्प दिखाया है। उसके ऐसे कार्यों में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर प्रावधान भी शामिल हुआ। ऐसे सभी मसलों पर उसे विपक्ष के नकारात्मक हमले झेलने पड़े,लेकिन वह विचलित हुए बिना आगे बढ़ती रही। उंसकी इसी इच्छाशक्ति का परिणाम है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार विधेयक दोनों सदनों से पारित हुआ। इसका विरोध करने वालों को निराशा हाँथ लगी। वह विधेयक को रोक भी नहीं सके, और उनकी वोटबैंक सियासत भी बेनकाब हो गई।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राष्ट्रीय नागरिकता विधयेक की मूल भावना को या तो समझने का प्रयास नहीं किया, या उन्होंने इसके मुकाबले वोटबैंक राजनीति को ही महत्व दिया। यही कारण था कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष विधेयक पर कोई भी तर्कसंगत विचार प्रस्तुत करने में विफल रहा। दोनों ही सदनों में वह संविधान,संविधान निर्माताओं, मुस्लिम, दलित आदि शब्द हो दोहराता रहा। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर विधयेक के माध्यम से इनमें से किसी की भावना आहत ही नहीं होनी थी। विपक्ष के भाषण का पूर्वोत्तर भारत में प्रतिकूल प्रभाव हुआ। जबकि इससे भारतीय नागरिकों को संतुष्ट होने चाहिए था। इसके माध्यम से उनके संसाधनों पर अवैध घुसपैठियों की हिस्सेदारी पर नियंत्रण स्थापित होने का प्रावधान किया गया। था।

विपक्ष ने कहा कि सरकार ने संविधान का उल्लंघन कर दिया है, संविधान निर्माताओं के अपमान किया है। विधेयक नहीं बल्कि विपक्ष की दलीलों से संविधान निर्माताओं के अपमान हुआ है। संविधान निर्माताओं ने यह मंशा कभी नहीं थी अवैध घुसपैठिये भारत को अपना ठिकाना बना लें, धीरे धीरे वह नागरिकता हासिल कर लें, मतदाता सूची में उनके नाम शामिल हो जाये, फिर वह चुनाव लड़े और विधि निर्माण और शासन में हिस्सेदारी करने लगे। विपक्ष को सोचना चाहिए था कि उनके तर्क न केवल संविधान की भावना के प्रतिकूल है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी उल्लंघन करने वाले है।

संविधान निर्माता राष्ट्रीय एकता,अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे। संविधान का अनुच्छेद तीन सौ बावन इसका प्रमाण है। इसमें आपात कालीन उपबन्ध किया गया। जब एकता अखंडता सुरक्षा संबन्धी चुनौती हो तो केंद्र सरकार इस अनुच्छेद का प्रयोग कर सकती है। इससे उसको असीमित अधिकार प्राप्त होते है। इसका निहितार्थ यह है कि एकता अखंडता सीमाओं की सुरक्षा से बढ़ कर कुछ भी नहीं है। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान जैसे शत्रु मुल्क है। बंगलादेश में जब शेख हसीना की सरकार होती है, तब तो गनीमत। अन्य कोई सरकार होती है तो वह भारत के विरोध में कार्य करती है।

इन पड़ोसियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बड़े षड्यंत्र के तहत अवैध रूप से घुसपैठ करा सकते है। राष्ट्रीय संकट के समय ये आंतरिक संकट उतपन्न कर सकते है।

इसलिए प्रत्येक देश अवैध घुसपैठियों के प्रति कठोर रुख रखते है। कई मुल्क ऐसे है जिनमें कोई अवैध ढंग से घुसपैठ कर ही नहीं सकता। दशकों पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकारों के समय बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठ को अंजाम दिया गया। वोटबैंक की सियासत में इसको रोकने की कौन कहे, इसे बढ़ावा दिया गया। आज यह पूर्वोत्तर ही नहीं पूरे देश के लिए समस्या बन गए है।लोकसभा में कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोले। उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरा बन सकती है। ऐसा लगा कि उनका पूरा ध्यान वोटबैंक सियासत पर ही केंद्रित है। राज्यसभा में भी इसी प्रकार के विचार सुनने को मिले। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मौन रहे। लेकिन राजनीति पर उतने ही मुखर थे। कहा कि इस बिल को लेकर जल्दबाजी क्यों हो रही है, संसदीय कमेटी के पास इसे भेजा जाता और तब लाया जाता। आनंद शर्मा इसे जल्दीबाजी बता रहे है, जबकि इस प्रकार का विधेयक कई दशक पहले आना चाहिए था। तब अवैध घुसपैठ की समस्या इतनी विकराल न हुई होती। इसी के साथ पाकिस्तान व बांग्लादेश में प्रताड़ित हिन्दू, बौद्ध,सिख आदि को भी न्याय मिल जाता। इनके लिए तो भारत के अलावा दुनिया में कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन विपक्षी सदस्य इनके लिए चिंतित दिखाई नहीं दिए। विरोधियों ने इस बिल को संवैधानिक, नैतिक आधार पर गलत बताया, प्रस्तावना के खिलाफ कहा। संविधान में कहीं भी अवैध घुसपैठ के प्रति आंख बंद रखने की बात नहीं कही गई। इसके विपरीत राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल की पूर्व सरकारों ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देकर संविधान की भावना का उल्लंघन किया था। नरेंद्र मोदी सरकार अवैध घुसपैठ को रोकने का प्रयास कर रही है। यही संविधान का सम्मान है। इसी प्रकार कांग्रेस के नेता ने इस बिल को प्रस्तावना के खिलाफ बताया।

प्रस्तावना हम लोग शब्द से शुरू है, यह हम लोग भारत के नागरिक है। इसमें अवैध घुसपैठी शामिल नहीं है। यह सही है कि संविधान सभा में नागरिकता पर व्यापक चर्चा हुई थी। यह भी सही है कि भारत के संविधान में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। बंटवारे के बाद जो लोग यहां पर आए उन्हें सम्मान मिला है। पाकिस्तान से आए दो नेता प्रधानमंत्री भी बने हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान व बांग्लादेश से पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार घुसपैठ हुई है, उस पर नए सिरे से विचार की आवश्यकता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने यही किया। इसी आधार पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर विधेयक लाया गया।अमित शाह ने ठीक कहा कि भारत के मुसलमान भारतीय नागरिक थे। वह अब भी नागरिक हैं और आगे भी भारत के नागरिक रहेंगे। बिल के बारे में गलत सूचना फैलाई गई कि यह विधेयक भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। उन्नीस सौ पच्चासी में असम समझौता हुआ। राज्य की स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए खंड छह में प्रावधान है। शाह ने कहा कि इसकी निगरानी के लिए समिति के माध्यम से एनडीए सरकार असम के अधिकारों की रक्षा करेगी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन कमेटी का हिस्सा है। यह विधेयक मिजोरम में लागू नहीं होगा। भारत दुनिया भर के मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता नहीं दे सकता। उत्पीड़न का सामना करने वाले तीन देशों के अल्पसंख्यकों के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। भारत को पाकिस्तान व बांग्लादेश की नजर से नहीं देखा जा सकता। वहां अल्पसंख्यको का अस्तित्व दांव पर लगा है। धार्मिक अल्पसंख्यक या तो मारे गए या वह शरण लेने के लिए भागकर भारत आ गए। ऐसे लोगों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी। सरकार ने नागरिकता रजिस्टर विधेयक के माध्यम से यही किया है। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच जैसे वोटबैंक की प्रतिष्पर्धा चल रही थी। ये लोग अपने को दूसरे के मुकाबले मुसलमानों का हितैषी साबित करना चाहते थे। संसद की बहस का इन्होंने इसी रूप में उपयोग किया। जबकि इस बिल में भारत के मुस्लिम नागरिकों का भी हित जुड़ा था। इनको मिलने वाले लाभ व सुविधाओं में अवैध घुसपैठी दखल देने लगे थे। कपिल सिब्बल,पी चिदम्बरम सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस पूरी चर्चा को वोटबैंक की सियासत की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। उन्हें जिन्ना का द्विराष्ट्रवाद याद आ रहा था। लेकिन इन्होंने इस बात का जबाब नहीं दिया कि किसी देश में अवैध घुसपैठियों की संख्या जब बेतहाशा बढ़ती है, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है।

यह बात कई दशक पहले जाहिर हो गई थी कि अवैध घुसपैठ के कारण धीरे धीरे असम अनेक जिलों में मूल भारतीय ही अल्पमत हो जाएंगे। इससे बड़ा खतरा यह होगा कि ये विदेशी घुसपैठी विधायिका व कार्यपालिका का हिस्सा बनने लगेंगे। यह बात कई दशक पहले जाहिर हो गई थी कि अवैध घुसपैठ के कारण धीरे धीरे असम अनेक जिलों में मूल भारतीय ही अल्पमत हो जाएंगे। इससे बड़ा खतरा यह होगा कि ये विदेशी घुसपैठी विधायिका व कार्यपालिका का हिस्सा बनने लगेंगे।

देश में जल्लादों की कमी

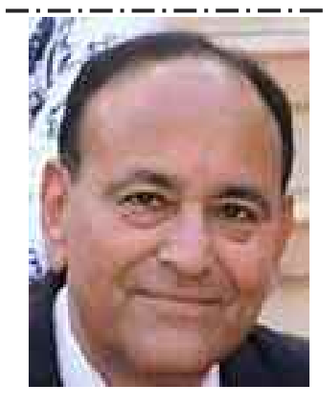

मीडिया में बारबार यह खबर चल रही है कि देश में जल्लादों की कमी है। यह खबर चैंकाने वाली है और सोचने के लिए विवश करने वाले की है कि जल्लाद नहीं होने के कारण सजायाफ्ता मुजरिमों को फांसी की सजा नहीं दी जा पा रही, यानी फांसी की सजा पर अमल नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि देश में फांसी के दर्जनों दर्जनों मामले लंबित हैं, लेकिन देश में मात्र दो ही जल्लाद हैं, जिस कारण कानून से सजा पाए अपराधियों को उनकी सजा के अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। देश में अंतिम फांसी 4 साल पहले 2015 में याकूब मेनन को दी गई थी। उसके बाद अभी तक किसी अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकी है। यह खबर पढ़कर विरोधाभासी प्रतीत होती है कि देश में जल्लादों की कमी है, जबकि हम रोज रोज ना सिर्फ समाचार पत्रों में जल्लादों के किस्से पढ़ते हैं। गाहे बगाहे अपने आसपास में भी जल्लादों को देखते रहते हैं। हम उन्हें जानते भी है, कुछ को पहचान भी लेते हैं, मगर फिर भी यही कहा जाता है कि जल्लादों की कमी नहीं है। उदाहरण आश्रमों मठों में साध्वियों का यौन शोषण किया जाता है। 46 साल की बच्ची को उसी स्कूल का टीचर रेप करके मार डालता है या जनप्रतिनिधि कहलाने वाले देश के कथित पथ दर्शक बने नेतागण सरकार के सौजन्य से चलने वाले अनाथ आश्रमों में रहने वाली नाबालिग बालिकाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते रहते हैं। चॉकलेट टॉफी का लालच देकर छोटेछोटे बच्चों का बुजुर्ग लोग यौन शोषण करने से बाज नहीं आते। ऐसे चेहरे बारबार सामने आते रहते हैं। इसके अलावा मोबलीचिंग का मामला हो या अन्य कोई हिंसक भीड़ का कृत्य, वह भीड़ ही जल्लाद के रूप में नजर आती है। यह भीड़ निर्दोष आदमी को और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों को अपने आक्रोश का शिकार बना कर दरिंदगी पूर्ण मौत का रास्ता दिखा देती है। इसके बावजूद कहा जाता है कि जल्लादों की कमी है। देश में सिर्फ उन जल्लादों की कमी

नजर आती है, जिनका पेशा ही यह है और जो कानून को अंजाम देने के लिए यह कार्य करते हैं। जिनकी जिम्मेदारी यह है कि कार्य कानून से सजा पाए अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना यानि फांसी पर लटकाना होता है। उन जल्लादों को तो कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। उन जल्लादों को से लोग नफरत करते हैं व उनसे दूर रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति इनकी तरह पेशे से जल्लाद नहीं बनना चाहता। समाज के नजर में अपने आपको जल्लाद घोषित कोई नहीं करना चाहता, मगर जहां कृत्य राक्षसी प्रवृत्ति जैसे हो, उन्हें जल्लाद कहने यह समझने में आप हम डर जाते हैं, हिचक जाते हैं। कटु सत्य यह है कि कानून के निर्णय को अंजाम देने वाले जल्लाद सम्मान के पात्र होने चाहिए। वह तो कानून सम्मत काम करते हैं और जल्लादों जैसे दरिंदों को से समाज को मुक्ति दिलाते हैं, मगर अपने भारत देश में तो उल्टा हो रहा है। कटु सत्य यह भी है कि वहशी हत्यारों और नाबालिग बच्चियों के साथ अमानुशिकार कृत्य करने वाले दरिंदों को अच्छे अच्छे वकील बचाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं और कई बार बचा भी जाते हैं। उन्हें ना तो जल्लाद कहा जाता है और ना ही हम उन्हें शर्म की दृष्टि से देखते हैं। बस हमारी धारणा यही बनी हुई है कि जो पेशे से जल्लाद हैं वह हेय हैं निकृष्ट व्यक्तित्व है, जबकि यह जल्लाद तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फांसी के सजा देकर समाज का एक प्रकार से भला ही करते हैं। आप हम सभी उन सफेदपोश जल्लादों को भूल जाते हैं, जो बलात्कार की पीड़ित को जलाकर मार देते हैं। विडंबना की बात यह है कि हमारे आसपास रहने वाले सफेदपोश जल्लाद, जो कानून को जेब में रखते हैं व कानून की परवाह नहीं करते हैं, उनकी समाज भी अनदेखी कर रहा है। वह जल्लाद ना ही अपने कृत्य के प्रति अफसोस करते हैं और न ही वह माफी की भावना तक रखते हैं। जबकि वास्तव में असली जल्लाद तो वह है। शायद यही कारण हो सकता है कि इस प्रकार के जल्लादों के सामने कानून के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए जल्लाद बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। इसी कारण कानूनी जल्लादों की कमी से देश में हो रही है। जबकि दरिंदगी करने वाले जल्लाद हर वर्ग, हर कौम, हर धर्म और हर स्थान पर बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके बावजूद भी देश में जल्लादों की कमी कहा जाना अतिशयोक्ति लगती है और विडंबना की बात प्रतीत हो रही है।

श्याम सुन्दर जैन
सादुलपुर , जिला चूरू
राजस्थान।

दुष्कर्म पीड़िताओं को मिले त्वरित इंसाफ

हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार कर उसे जिंदा जलाने के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। बलात्कार के आरोपियों कि पुलिस एनकाउंटर में मौत को लेकर विभिन्न तरह के सवाल उठ सकते हैं। लेकिन चारों बलात्कारियों की पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की खबर के बाद देशभर में जो प्रतिक्रिया हुई है वह हमारी कानून व्यवस्था व न्यायपालिका के समक्ष एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। देशभर में लोगों ने पुलिस एनकाउंटर की तरफदारी करते हुए उसे जायज ठहराने की बात कही है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने चारों बलात्कारियों का एनकाउंटर कर अपराधियों में डर का माहौल पैदा किया है। पुलिस की इस कार्यवाही की सराहना की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर देश भर से लोग पुलिस के पक्ष में खुलकर समर्थन जता रहें हैं।

पुलिस एनकाउंटर सही था या गलत यह तो न्यायिक जांच का विषय हैं। लेकिन पुलिस हिरासत में जिस तरह से चारों बलात्कार के आरोपी मारे गए हैं। उस पर देश की जनता ने जो प्रतिक्रिया दी है उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत धीमी गति से चल रही है। आधुनिक तकनीकी वाले इस दौर में देश के लोग चाहते हैं कि अपराधियों को सजा देने में लंबा समय नहीं लगाया जाना चाहिए। लोगों का मानना है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को अविलम्ब कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देश के कई राज्यों ने नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को फांसी देने का कानून भी बनाया है मगर आज तक एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं हो पाई है। आज से 7 वर्ष पूर्व दिल्ली में निर्भया बलात्कार कांड के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने के बावजूद उन्हे अभी तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया ला सका है। राजस्थान के अलवर में 7 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

बाड़मेर के जिला न्यायालय मे एक 12 साल की मासूस से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। मगर अभी तक एक भी दोषी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सका है। जिससे अपराधियों में डर व्याप्त नहीं हो पाया है। इससे देश के लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति निराशा का भाव पैदा होता है। उसी की प्रतिक्रिया में लोग हैदराबाद पुलिस के एनकाउंटर को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक रेप पीड़ित लड़की को अभियुक्तों ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है। लड़की की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गयी है। पीड़ित लड़की का शरीर आग में 90 फीसदी तक झुलस चुका था। लडक़ी का कसूर यह था कि उसने बीते मार्च महीने में अपने साथ हुए गैंगरेप की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। लड़की उसी मुकदमे के सिलसिले में रायबरेली जा रही थी। स्टेशन जाते समय पांच लोगों ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। अभियुक्त कुछ दिन पूर्व ही जेल

से जमानत पर बाहर आए थे। यदि मुजरिमो को तुरंत सजा मिल जाती तो वो जेल से बाहर आकर इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर पाते। मगर सामूहिक बलात्कार के आरोपी को भी कोर्ट से जमानत मिलना यह सवाल खड़ा करता है ऐसे अपराधियों को जमानत कैसे मिल जाती है। राजस्थान के टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पहली कक्षा में पढने वाली 6 साल की मासूम से एक व्यक्ति ने बलात्कार कर उसका गला घोट कर हत्या कर दी। बलात्कारी ने भेद खुलने के डर से उस मासूम का इतने दर्दनाक तरीके से गला दबाया कि उसकी आंखें भी उबल कर बाहर निकल आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अन्य किसी मासूम के साथ ऐसी घटना की पुनरावृति ना हो इस बाबत कुछ भी कहने से उन्होने कन्नी काट ली। देश में आये दिन हो रही बलात्कर की घटनायें कब रुकेगी इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब के नाम पर राज्य सरकारें आंकड़ा गिनाने लगती हैं कि अब हमारे राज्य में ऐसी घटनाये कम हो रही हैं। भारत में कहा जाता हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता- यानि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता रमते हैं।

मगर इसके उलट हमारे समाज में हर रोज, हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। विडम्बना यह है कि अन्य स्थानों के साथसाथ स्कूलों तक में ऐसे अपराध हो रहे हैं। आज कल देश में दुष्कर्म की ऐसी ऐसी घटनाए सामने आ रही है की आम आदमी का इंसानियत पर से विश्वास ही खत्म हो रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2017 के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि दुष्कर्म और यौन शोषण के मामलों में बेहद बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार तीसरे साल भी वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश में हुए अपराध के वर्ष 2017 के नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वर्ष 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के तीन लाख 59 हजार 849 मामले दर्ज किए गए। 2016 में तीन लाख 38 हजार 954 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2015 में तीन लाख 29 हजार 243 मामले दर्ज किए गए थे। इन अपराधों में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, एसिड हमले, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता और अपहरण आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अधिकतम मामले उत्तर प्रदेश 56,011 में दर्ज किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र में 31,979 मामले, पश्चिम बंगाल में 30,992, मध्य प्रदेश में 29,778, राजस्थान में 25,993 और असम में 23,082 मामले दर्ज किए गए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक 2017 में भारत में 32,559 बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुयी थी जिनमें मध्य प्रदेश में 5 हजार 562 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये। बारह साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा का बिल आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 संसद से पारित हो गया है। इस संबंध में 21 अप्रैल को एक अध्यादेश लागू किया गया था। देश के कई इलाकों में बच्चियों के साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की घटनाओं के बाद यह अध्यादेश लागू किया गया था। इस विधेयक के तहत 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म करनेवाले को सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महिला सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। राजस्थान में एक कार्यक्रम में बोलते हुये उन्होंने कहा पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

संसद को दया याचिकाओं के इस विषय पर संविधान संशोधन के बारे में विचार करना चाहिए। संविधान ने दया याचिका का अधिकार दिया है। लेकिन पॉक्सो एक्ट के दोषियों को ऐसे किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है।

भारत में कई कानून बनने के बाद भी दुष्कर्म की घटनाये लगातार जारी हैं। रोजाना अलगअलग राज्यों से बलात्कार होने की खबरें आती रहती हैं। एक सभ्य समाज के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए। समाज में व्याप्त इस प्रकार की सबसे बड़ी बुराई से छुटकारा कैसे मिले इसका जवाब किसी के पास नहीं हैं। हर कोई सरकार व पुलिस के भरोसे बैठा हुआ है। देश में सिर्फ कानून बना देने से ऐसी घटनाओ पर रोक लगा पाना सम्भव नहीं है। इसको रोकने के लिये समाज को भी आगे आना पड़ेगा।

रमेश सर्राफ झुंझुनू
राजस्थान 9414255034

डेंगू का कब्जा, थमी सबकी सांसे

देशभर में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। शहर हो देहात हर जगह डेंगू से मौते हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक हर का कोई न कोई सदस्य डेंगू की चपेट में है। हर रोज डेंगू के दो दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो रही है। चिकित्सकों के मुताबिक दिसम्बर का पूरा महीना डेंगू के आतंक से प्रभावित रहेगा। इस मौसम में मच्छरों के पनपने की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। डेंगू बुखार से बचने के भी तरीके हैं। अगर इस मौसम में कुछ सावधानियां गंभीरतापूर्वक बरतेंगे तो डेंगू से बचे रहेंगे। अभी तक डेंगू के बुखार या एडीज मच्छर के वायरस से परेशानी होगी। मौसम में ठंडापन बढ़ने से मरीजों की संख्या में कमी आएगी

फिरहाल, डेंगू चिकनगुनिया के साथ साथ मलेरिया, फाइलेरिया, चर्म रोग, डायरिया से निपटना इस वक्त चिकित्सकों के लिए चुनौती है। इसके लिए घर घर ब्लीचिंग पाउडर और चूना छिड़काव के साथ ही पानी पीने योग्य बनाने के लिए हैलोजेन टैबलेट बंटवाने की जरुरत है। नागरिकों को चाहिए कि वे अपने आसपास सफ़ाई रखे। पानी उबालकर पीए, मच्छरदानी का उपयोग करें। हालांकि सरकार की तरफ़ से जो दावे किए जा रहे है वो अस्पताल में आकर ही खोखले साबित होते हैं। जबकि अस्पतालों में सबसे अच्छी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अस्पताल के इमरजेंसी हो या अन्य वॉर्ड मरीज और उनके परिजनों के पास अस्पताल की व्यवस्था को लेकर शिकायतों के अंबार है। हाल यह है कि डॉक्टर खुद देखने नहीं आते, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती, नर्सिंग स्टॉफ़ काम काज में लापरवाही बरतता है। वार्ड की गंदगी से हमेशा संक्रमण का डर बना रहता है। लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। हर घर में बच्चे बीमार चल रहे हैं, कुछ तो अस्पताल में भर्ती हैं। लोग बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, पता नहीं कब बीमार हो जाए। आंकड़ों के अनुसार हर साल पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोग डेंगू का शिकार होते हैं। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के करीब 125 देश डेंगू की चपेट में हैं। डेंगू एक चक्र में देखी जाने वाली बीमारी है। और कुछ साल बाद अचानक किसी साल ये महामारी सी दिखती है। इस साल बढ़े मामलों के पीछे जलवायु परिवर्तन को बड़े कारण के तौर पर देखा जा रहा है।

डेंगू संक्रामक बीमारी है, जो चार में से किसी एक प्रकार के डेंगू वायरस के सीरोटाइप के कारण होती है। यह मादा एडिस एजिप्टि मच्छर के काटने से फैलती है। आरंभिक लक्षण हैं अचानक तेज बुखार, शरीर में रैशेज, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, आंख हिलाने में दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना आदि। जोड़ों में जबरदस्त दर्द होने के कारण डेंगू का एक नाम 'ब्रेक कोन फीवर' भी है। मिचली, उल्टी, भूख न लगना भी सामान्य लक्षण हैं। बुखार तो दस दिनों में ठीक हो जाता है, पर पूरी तरह ठीक होने में एक महीना लग सकता है। बड़े बच्चे व व्यस्कों को छोटे बच्चों के मुकाबले अधिक सताता है। कुछ मामलों में यह हेमोरेजिक फीवर का रूप लेता है। बच्चों, व्यस्कों में होनेवाला डेंगू हेमोरेजिक पांच फीसदी मामलों में जानलेवा होता है। शहरीकरण के बढ़ते प्रचलन और बदलती जीवनशैली के कारण हाल के वर्षों में ग्रामीण इलाकों व उपशहरी इलाकों में डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है। डेंगू के इलाज के लिए अभी तक कोई विशेष दवा ईजाद नहीं की जा सकी है। सिर्फ लक्षणों के आधार पर दवाइयां दी जाती हैं। इसलिए सावधानी व सचेत रहने की जरुरत है। अगर किसी को डेंगू का अंदेशा हो, तो वह पैरासिटामोल की गोलियां ले सकता है, मगर एस्परिन लेने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को आराम करना चाहिए। अधिकसेअधिक तरल पदार्थ का सेवन करें तथा डॉक्टर से परामर्श लें। जब तक बुखार कम न हो तब तक एक खुले व ठंडे कमरे में बिस्तर पर आराम करें। शरीर में दर्द व ज्वर को कम करने के लिए क्रोसिन (पैरासिटामोल) की गोली लें।

ठंडे पानी की पट्टी करें। गुनगुने पानी से स्पॉन्ज या स्नान करें। डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए अधिक तरह पदार्थ लें, जैसे पानी, ओआरएस, सब्जियों, फलों का रस। बिना तेल का हल्का भोजन करें। कॉफी, चाय, साफ्ट ड्रिंक न पीएं। टीवी न देखें व ऐसा कोई काम न करें, जिससे दिमाग पर जोर पड़े। डेंगू बुखार में अक्सर प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। इससे पीड़ित मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत होती है। डेंगू बुखार से ग्रसित व्यक्ति के यदि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो पपीते के पत्ते ब्लड प्लेटलेट्स काउंट में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कप पपीते का ताजा पत्ता लीजिए। इसे

पीस कर जूस निकालें और मरीज को पिलाएं। इसमें शहद या फिर फलों का जूस मिला सकते हैं। इससे स्वाद बदल जाता है। गिलोय, एलोवेरा और अनार का जूस भी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में सहायक हैं। हर चार घंटे या दिन में 34 बार इन चारों के 5050 ग्राम जूस पीने से डेंगू में लाभ पहुंचता है। बता दें, देश के अनेक राज्यों में हर साल डेंगू का कहर देखा जाता है। हजारों लोग डेंगू से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती होते हैं। जिनमें से कई दर्जन लोग मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। ऐसे में डेंगू के मामलों में हो रही बढ़ोतारी के साथसाथ इस रोग की भयावहता की चर्चा सर्वत्र होती है। हालांकि डेंगू की दस्तक तो प्रतिवर्ष सुनाई पड़ती है किन्तु हर तीन चार वर्ष के अंतराल पर डेंगू एक महामारी के रूप में उभरकर सामने आता है और तभी हमारी सरकारें तथा स्थानीय प्रशासन कुम्भकर्णी नींद से जागते हैं। प्रतिवर्ष मानसून के बाद देशभर में डेंगू के कई हजार मामले सामने आते हैं। डेंगू की दस्तक के बाद डॉक्टरों व प्रशासन द्वारा आम जनता को कुछ हिदायतें दी जाती हैं लेकिन डॉक्टर व प्रशासन इस मामले में खुद कितने लापरवाह रहे हैं, इसका उदाहरण डेंगू फैलने के बाद भी कमोवेश सभी राज्यों में जगहजगह पर फैले कचरे और गंदगी के ढ़ेर तथा विभिन्न अस्पतालों में सही तरीके से साफसफाई न होने और अस्पतालों में भी मच्छरों का प्रकोप हर साल देखकर स्पष्ट रूप से मिलता रहा है। प्रशासनिक लापरवाही का आलम यही रहता है कि ऐसी कोई बीमारी फैलने के बाद एकदूसरे पर दोषारोपण कर जिम्मेदारी से बचने की होड़ दिखाई देती है।

डेंगू का प्रकोप अब पहले के मुकाबले और भी भयावह इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अब डेंगू के कई ऐसे मरीज भी देखे जाने लगे हैं, जिनमें डेंगू के अलावा मलेरिया के भी लक्षण होते हैं और दोनों बीमारियों के एक साथ धावा बोलने से कुछ मामलों में स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। डेंगू के कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जब सप्ताह भर बाद ही रोगी के शरीर में ज्यादातर अंगों ने काम करना बंद कर देते हैं और रोगी दम तोड़ देता है। कुछ ऐसे भी मरीज मिले हैं, जिनमें डेंगू के शिकार होने के बावजूद बुखार और तेज सिरदर्द जैसे डेंगू में आम लक्षण नदारद थे बल्कि वे केवल शारीरिक थकान की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनमें रक्त जांच के बाद डेंगू की पुष्टि हुई। आमतौर पर सामने आने वाले लक्षणों रहित ऐसे मामले डॉक्टरों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। डेंगू बुखार एक वायरल संक्रमण है। यह एक खतरनाक बीमारी है, जो ऐडीस मच्छर के काटने से होती है, जो हमारे घरों के आसपास खड़े पानी में ही पनपता है। ऐडीस मच्छर काले रंग का स्पॉटेड मच्छर होता है, जो प्रायः दिन में ही काटता है। डेंगू का वायरस शरीर में प्रविष्ट होने के बाद सीधे शरीर के प्रतिरोधी तंत्र पर हमला करता है। इस मच्छर का सफाया करके ही इस बीमारी से पूरी तरह से बचा जा सकता है। प्रायः मानसून के बाद ही डेंगू के ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। डेंगू प्रायः दो से पांच दिनों के भीतर गंभीर रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को बुखार आना बंद हो सकता है और रोगी समझने लगता है कि वह ठीक हो गया है लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है बल्कि यह स्थिति और भी खतरनाक होती है। अतः बेहद जरूरी है कि आपको पता हो कि डेंगू बुखार होने पर शरीर में क्याक्या प्रमुख लक्षण उभरते हैं। डेंगू के अधिकांश लक्षण मलेरिया से मिलते जुलते होते हैं लेकिन कुछ लक्षण अलग भी होते हैं। तेज बुखार, गले में खराश, ठंड लगना, बहुत तेज सिरदर्द, थकावट, कमर व आंखों की पुतलियों में दर्द, मसूडों, नाक, गुदा व मूत्र नलिका से खून आना, मितली व उल्टी आना, मांसपेशियों व जोड़ों में असहनीय दर्द, हीमोग्लोबिन के स्तर में वृद्धि, शरीर पर लाल चकते (खासकर छाती पर लाललाल दाने उभर आना), रक्त प्लेटलेट (बिम्बाणुओं) की संख्या में भारी गिरावट इत्यादि डेंगू के प्रमुख लक्षण हैं। बीमारी कोई भी हो, उसके उपचार से बेहतर उससे बचाव ही होता है और डेंगू के मामले में तो बचाव ही सबसे बड़ा हथियार माना गया है। उचित सावधानियां और सतर्कता बरतकर ही इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। घर की साफ सफाई का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। आपके घर या आसपास के क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप न हो, इसके लिए जरूरी है कि मच्छरों के उन्मूलन का विशेष प्रयास हो। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का पनपना रोकें। निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान दें: अपने घर में या घर के आसपास पानी जमा न होने दें। जमा पानी के ऐसे स्रोत ही डेंगू मच्छरों की उत्पत्ति के प्रमुख कारक होते हैं। यदि कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसमें केरोसीन ऑयल या पैट्रोल डाल दें ताकि वहां मच्छरों का सफाया हो जाए। पानी के बर्तनों, टंकियों इत्यादि को अच्छी प्रकार से ढ़ककर रखें। कूलर में पानी बदलते रहें। यदि कूलर में कुछ दिनों के लिए पानी का इस्तेमाल न कर रहे हों तो इसका पानी निकालकर कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर कूलर को सुखा दें। खाली बर्तन, खाली डिब्बे, टायर, गमले, मटके, बोतल इत्यादि में पानी एकत्रित न होने दें। बेहतर यही होगा कि ऐसे कबाड़ और इस्तेमाल न होने वाले टायर इत्यादि को नष्ट कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी पानी जमा होकर सड़ न रहा हो। घर के दरवाजों, खिड़कियों तथा रोशनदानों पर जाली लगवाएं ताकि घर में मच्छरों का प्रवेश बाधित किया जा सके। पूरी बाजू के कपड़े पहनें। हाथपैरों को अच्छी तरह ढ़ककर रखें। मच्छरों से बचने के लिए मॉस्कीटो रिपेलेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना मच्छरों से बचाव का सस्ता, सरल, प्रभावी और हानिरहित उपाय है।

रोगी को हर हाल में पौष्टिक और संतुलित आहार देते रहना बेहद जरूरी है। डेंगू होने पर तुलसी का उपयोग बेहद लाभकरी है। आठदस तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर लें या तुलसी के 1015 पत्तों को एक गिलास पानी में उबाल लें और जब पानी आधा रह जाए, तब पी लें। नारियल पानी पीएं, जिसमें काफी मात्रा में इलैक्ट्रोलाइट्स होते हैं, साथ ही यह मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है, जो शरीर में ब्लड सेल्स की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं।

सुरेश गांधी

कमजोर सिस्टम है वजह ऐसी घटनाओं का

हैदराबाद में डॉ प्रियंका रेड्डी के साथ हुए दुष्कर्म ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। साथ में और भी घटनाओं ने आखिर क्यों?इस तरह की घटनाएं बारबार सामने क्यों आ रही है? हालांकि एनकाउंटर में उन चारों आरोपियों की मौत हो गई है ।कुछ पल के लिए सभी के चेहरे पर सुकून आया लेकिन हासिल क्या हुआ उन चारों के मारे जाने के बाद क्या घटनाओं पर अंकुश लग जाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं।आखिर हालात कैसे सुधरेंगे फिर? यह भी एक सवाल है। मेरे ख्याल से तो फास्ट ट्रायल से जिस तरह मध्यप्रदेश में है। फास्ट ट्रायल में सुनवाई के बाद कोई भी आगे कोर्ट में इससे जुड़े केस नहीं कर पाए ऐसा नियम भी होना चाहिए।रेप से जुड़े केस में फैसला तुरंत होना ही चाहिए।फास्ट ट्रायल द्वारा आरोपियों के अपराध साबित होने पर सजा तुरंत हो। दुसरी बात हमारा सिस्टम ही कमजोर है।जब सिस्टम ही कमजोर है तो कोई नियम कानून इसे रोक नहीं सकता जब तक मजबूत सिस्टम ना हो। जरूरत है मजबूत सिस्टम और तुरंत एक्शन लेने की। केवल कार्रवाई से घटनाएं रुक नहीं सकती क्योंकि डर है ही नहीं हमारे सिस्टम का उन्हें। उन्हें पता है हमारा सिस्टम बेहद कमजोर है, पुलिस की लापरवाही और परिवार का समय न देना भी एक बहुत बड़ी वजह है ऐसी घटनाओं की। परिवार के लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए उनके बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं,क्या कर रहे हैं। फोन पर पोर्न पिक्चर और नशा कर के ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।कम उम्र में गलत संगत का असर है कि अपने बड़ों के साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को देखना होगा, समझना होगा अगर उन्हें लगता है बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें छोड़ने की बजाय किसी की मदद लेनी चाहिए ना की उन्हे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग गलत संगत में जाते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। बचपन से सही, गलत समझाना, रिश्तो को मान सम्मान,इज्जत देना सिखाएं। हैदराबाद की घटना से समझना होगा। हमारा सिस्टम कमजोर है तो मजबूत बनानी होगी पुलिस को लापरवाही खत्म कर सख्त कदम उठाने ही होंगे।अगर आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी है तो हालात सुधारने के लिए सजा देनी ही होगी,जिससे लोगों को सबक भी मिले।रेप के बाद हत्या में तुरंत फांसी होनी चाहिए। जिससे इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों में डर पैदा हो।सब कुछ हमारे सिस्टम पर निर्भर है जिस दिन हमारा सिस्टम मजबूत होगा उस दिन इन घटनाओं पर अंकुश जरूर लगेगी।

निक्की शर्मा रश्मि
मुंबई (मीरा रोड)

सामाजिक व्यवसाथा में जुर्म का कोई स्थान नही है चाहे वह किसी प्रकार का क्यूँ न हो?सभी जुर्म के लिए संविधान में दंड का प्रावधान है जो विभिन्न संस्थाओ द्वारा जुटाये गये सबूत और रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में जिस प्रकार से रेप की क्रूरतापूर्ण घटनाएँ का वीभत्स रूप देखने को मिला है शायद सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित और सख्त सजा दी जाय शायद न्याय भी यही कहता है।आखिर आधी आबादी पर ही क्रूर मानसिकता विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग अपना शिकार क्यों बनाते है क्या सरकार और समाजशास्त्रीयों ने इस पर भी कभी अध्ययन किया।आज महिलायें असहज है तो क्यू? आखिर इसका इलाज तो करना होगा सामाजिक परिवेश को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले इन्टरनेट, चैनलो, धारावाहिक,विज्ञापनो और भी कई ऐसे स्त्रोत है जहाँ अश्लीलता खुल के परोसी जाती है जिस पर एक आचार संहिता के तहत कठोर नियम होनी चाहिए और वैसे धिरावाहिक या शार्ट फिल्म को बैन करना चाहिए जो अश्लीलता परोसते हैं।और ऐसे धारावाहिक ही दिखाई जाय जिसमें औरतो का सम्मान हो ज्ञानवर्द्धक हो ताकि वैसे लोग भी प्रेरणा ले सकें जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो रहे हैं।हलांकि सभी की गाईड लाईन हमारे संविधान में उपलब्ध हैं लेकिन शायद और सख्त होने की जरूरत अभी बाकी है।वैसी चीजे जो पूरे समाज को गंदा करती हो उन्हें बार बार दिखाना विभिन्न माध्यमो से खतरनाक साबित हो रहा है।

आज के इस डिजिटल युग में मीडिया की भूमिका भी अहम हो गयी है जिसे अब और सख्त होना होगा विशेषकर सामाजिक जागरण को लेकर उन्हें समाज को जगाना होगा। निष्पक्ष निडरता साहस और स्पष्टता के साथ महिलाओ की अहमियत और सम्मान उन विक्षिप्त मानसिकता वाले लोगो तक संदेश पहुँचाने का ससक्त मध्यम बनना होगा शायद वे ऐसा कर भी रहे लेकिन उन्हें लगातार करने की जरूरत है।

आये दिन लूट चोरी बालात्कार की ह्रदय विदारक घटनाओं ने देश और मानवता को घृणित किया है जिसकी कल्पना से रूह तक कांप जाती है।हाल में घटित काण्ड,ऐसी जघन्यता आखिर समाज में रहने वाले लोग कैसे और क्यूँ करने लगे हैं इतनी कटुता क्यों उमड रही है? यह राक्षसी प्रवृत्ति का खात्मा बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसे बढते मोबाइल का प्रयोग मानते है तो कुछ लोग छोटे कपडो का चलन पर जहा तक मोबाइल का सवाल है उसमे अच्छी और सकारात्मक सोच भी है जैसी सोच होगी वैसे आप यूज करेंगे जहां तक कपडो का सवाल है तो बच्चीयो मे कौन सी अश्लीलता दिखती है यह तो ओछी और विकृत मानसिकता के कारण है।

विकृत और विक्षिप्त मानसिकता वाले लोगो की हमारे देश मे अत्यधिक वृद्धि हुई है शाट काट से धन कमाना और ऐय्याशी करना उनका मुख्य उद्देश्य हो गया।दूसरा लड़कियो का लड़को से हर क्षेत्र में आगे निकलना और स्वावलम्बी होना ऐसी मानसिकता को जन्म देने लगा है जिससे द्वेष भरा एक माहौल समाज में बनता जा रहा है।आज सभी क्षेत्र में लडकियां अच्छा करने लगी है।जबकि लड़के वेरोजगार और पिछडते जा रहे है उनकी लगन एकाग्रता और

सहनशीलता अब देश का परचम लहरा रही है।अगर ऐसे में विक्षिप्त विकृत मानसिकता जन्म लेता है तो इसकी क्रूरता दिखाई पड़ने लगती है जो आये दिन दिख भी रहा है।

समाज में अपराध की कोई जगह नही है अपराधिक प्रवृति और सोच अब क्रूरता में परिवर्तित होने लगी है।एक दूसरे से घृणा, द्वेष करना और अपनी महत्वाकंक्षा को पूरा करने के लिये लोग घृणित और क्रूरता पर उतरने लगे हैं ।इस सोच को बदलना होगा। भारत एक सभ्य सांस्कृतिक और सहिष्णु राष्ट्र रहा है जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी तरह की क्रूरता हो समाज राष्ट्र और परिवार के लिए खतरनाक है। चाहे वह भीड़ में किसी को मारना हो, डायन बताकर अभद्रता और क्रूरता प्रदर्शित करना हो,तेजाब फेककर जलाना हो, दहेज दानवों द्वारा किया गया अपराध हो बदचलन बताकर की गयी क्रूरता हो या फिर बलात्कार समाज और लोग बर्दाश्त नही करते लेकिन आये दिन घटित होती है।यह क्रूरता तो अब घरों में भी प्रवेश करने लगी है।सरकारें या समाज की नीतियां तो हैं संविधान में दंड का प्रावधान भी है लेकिन घटनाओ को रोक पाने में सफलता नही मिलती ।सवाल हैं ऐसा क्यों होता है ? घटना घटने के बाद तर्क वितर्क जाँच अधिनियम को खंगाला जाता है जबकि सरकार के पास मौजूद तंत्र और एजेंसियाँ समय पर त्वरित सावधानी के साथ कार्य करे तो किसी भी घटना को रोका जा सकता है यह उनकी नैतिक जबाबदेही भी है । किसी निर्दोष की जान माल की रक्षा करना सरकार और वहाँ के प्रशासन की जिम्म्वारी होती है लेकिन ऐसा संभव नही हो पाता और लोग ना चाहते हुए भी मौत के आगोश मे समा जाते है जिसकी शिकार सबसे ज्यादा महिलाएँ है, फिर मुआवजो का दौर शूरू होकर वही समाप्त हो जाता है, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा क्या परिवर्तन सिर्फ सत्ता का होगा या फिर व्यवस्था की। जरूरत तो व्यवस्था परिवर्तन की है चाहे सरकारे किसी की भी हो। इस क्रूरता और अपराधिक सोच को बदलना होगा। किसी भी तरह का अपराध समाज के लिए विध्वंसक साबित होती रही है। ऐसे लोगो के खिलाफ वातावरण बनाना हमारा एक उद्देश्य या कार्य हो सकता है, जिसके लिए समाज को नैतिक जबाब देही के तहत कार्य करना आवश्यक है।ऐसी मानसिकता को रोकने की आवश्यकता है।

भारत की वैचारिक यात्रा ईश्वर सत्य से ही, शुरू होती है। यात्रा एक नया मंजिल ढूंढती है समाज से,सरकार से,जनप्रतिनिधि से तमाम व्यवस्थाओं से जो लोगो के लिए कार्य करते हुए उद्घोष करे ऐसी घटनाओ की सिर्फ निंदा नही घटने से रोकेगे तभी सही मायने में सत्य ही ईश्वर है होगा।लेकिन आजकल समाज में भी सत्य कहने और सत्य सुनने वाले दोनों की कमी हो गयी है जो अच्छे संकेत नही देते। राजनेताओ के मौन होने के कारण हो सकते हैं लेकिन समाज की प्रतिक्रिया आपेक्षित होती है जैसे हैदराबाद में दिखी।समाज अगर प्रतिक्रिया विहीन हो जाय तो पतन होना स्वभाविक है बढ़ती घटनाओं पर मौन रहने से भी यह हमें नहीं छोड़ने वाली। बदलते परिवेश के साथ समाज को कलान्तर की गौरवशाली सभ्यतासंस्कृति,परंपराओं, संस्कार,स्वाभिमान को बचाने के लिए कार्य करने की जरूरत है।विशेषकर बालात्कार जैसी वीभत्स घटनाओ पर तभी मृत्युदंड दिला पाएँगे उन गुनाहगारो को जो समाज मे रहकर बूरी नजर बनाये रखते हैं।

आशुतोष
पटना बिहार

जैसी कर्म वैसा फल- मृत्युदंड

आखिर कब बदलेंगे हम

अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक विवाह समारोह में शामिल होने का अवसर मिला, समारोह में पहुंच कर में बहुत खुश थी क्योंकि यह एक सामान्य विवाह न होकर समाज के उत्थान या यूं कहे की एक आपेक्षित बदलाव की जीती जागती तस्वीर थी। दो बिखरी हुई जिंदगियां एक बार फिर मुस्कुरा रही थी, जहा एक पुरुष को वापस अपनी जीवन संगिनी मिल रही थी तो वहीं एक पति को खो चुकी स्त्री को जीवनसाथी और उसकी नन्हीबिटिया को पिता का प्यार.सच पुनर्विवाह का उत्तम उदाहरण था मेरे सामने. वर और वधू एक दूजे के साथ पंडित के समक्ष बैठे , एक दूसरे को फूलों का हार पहनाया वर ने दुल्हन की सिंदूर से मांग भर दी, इसी बीच महिलाओं की आपस में कानाफूसी होने लगी की फेरे नहीं होंगे क्या...

उनकी बातों को सुनकर वर की दादी जो अपने आप को इस बदलाव का जनक दिखा रही थी चिल्लाकर ऊंची आवाज़ में बोली अब आप ही बताएं पंडितजी भला विधवा स्त्री के भी कभी फेरे कराए है आपने, उस वक्त में सोच रही थी की पंडित जी ज़रूर उनकी इस छोटी सोच में ज्ञान का दीपक जलाकर फेरे अवश्य करवाएंगे, परन्तु यजमान और जजमान दोनों ही दिखावा कर रहे थे... मन से शायद दादी पोते के लिए बहू नहीं विधवा को ही अपनाकर घर ले गई। में वहीं के वहीं खड़ी रह गई और अनायास ही मेरे मुंह से शब्द निकल गए... आखिर कब बदलेंगे हम।

डॉक्टर वर्षा महेश
मुंबई।

सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी मूलमंत्र

कुछ लोग विफलता के बाद निराश हो जाते हैं और प्रयास करना ही बंद कर देते हैं उनके दिमाग में सिर्फ नकारात्मक विचार आते हैं और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप विफलता को अपने दिमाग पर हावी न होने दें जो असफल होता है उन्हें बड़ा दुख पहुंचता है विफलता से निराशा बढ़ती हैं और उत्साह खत्म हो जाता है।

विफलता के बाद के विचार

1.लक्ष्य कठिन लगते हैं: वैज्ञानिकों ने लोगों से एक फुटबॉल को 10 बार गोलपोस्ट पर क्लिक करने के लिए कहा इसके बाद उनसे गोल पोस्ट की ऊंचाई और दूरी के बारे में पूछा गया अध्ययन से पता लगा कि जिन लोगों ने गोलपोस्ट को ऊंचाई और दूरी अधिक बताई थी वह लोग ज्यादा फेल हुए वही गोल पोस्ट की ऊंचाई और दूरी कम बताने वाले लोग ज्यादा सफल हुई है असफल होने से आत्मविश्वास पर असर पड़ता है जैसे कि लोगों को लक्ष्य पहुंच के बाहर लगा ।

2. जोखिम लेने से डर लगता है

इंसान जितना कम आत्मविश्वासी होता है वह उतना ही ज्यादा असफल होने के बारे में चिंतित रहता है इसलिए वह जोखिम लेने से भी घबराता है अगर आप पारंपरिक तरीके से काम में लेते हुए असफल हो जाते हैं तो आपको चुनौतीपूर्ण तरीके काम में लेने चाहिए ।

3. क्षमताओं पर सवाल

जब एक बार असफल हो जाते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है लक्ष्य कठिन प्रतीत होते हैं हमें लगता है कि लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे आत्मविश्वास का स्तर कम होने पर हमें डर लगता है कि

हम अब कभी कुछ नहीं कर सकते ।

4. असहाय महसूस होता है

एक बार जब किसी इंसान को एक काम में विफलता मिलती है तो वह असहाय महसूस करने लगता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता उसे लगता है कि उसमें कोई सामर्थ्य नहीं बचा है ।

सफलता की ओर कैसे बढ़े :

1. व्यवधानों से लड़े

इस बात को पहचाने की विफलता क्षमताओं के बारे में आपकी सोच को खराब कर देती है किसी भी हार के बाद कभी यह न सोचे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

2. गुणवत्ता ओं पर प्रकाश डालें

अपनी विफलता को भुला दें और उन गुणवत्ता ओं की सूची बनाएं जो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें ।

3. आपके लिए सफलता क्या है

खुद को प्रेरित करें कि आखिर आप पहली बार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में क्यों बड़े थे। सोचा कि अगर आप सफल हो गए तो आपको कैसा लगेगा ।

4. कैलकुलेटेड रिस्क या जोखिम लें

अगर आप गैर परंपरागत तरीके काम में लेते हैं तो बेचैनी होना स्वाभाविक हैं। कैलकुलेटेड जोखिम ले ।आपको हर विषय के बारे में अलगअलग तरह से सोचना होगा।

5. क्रिएटिविटी या रचनात्मकता जगाएं

नए तरीके से चीजों के बारे में सोचें । हर पहुंच की सूची बनाएं। विचारों के बारे में नकारात्मक ख्याल ना आने दें। अपनी क्रिएटिविटी या रचनात्मकता को जगाने का प्रयास करें।

6. कमी को दूर करें

अधिकतर असफल होने वाले अपनी अपर्याप्त योजनाएं और कमजोर सिध्दांतों के चलते इच्छित कामयाबी अर्जित न होने पर हताश हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि वे पर्याप्त स्पष्ट धारणा बनाकर कार्य शुरू करें। मनोवाछित सफलता प्राप्त नहीं होनें पर अंतह आत्मा को गहरा अघात लगता हैं और हताशा बढ़ती है और उत्साह पर कठोराघात पहुंचता हैं। साथ इससे आत्मविश्वास भी दब जाता है जिसका मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं। विफलता के उपरांत इससे उबारने के सकारात्मक तरीके अपनाकर स्वयं में सुधार लाया जा सकता हैं, जिससे बेहतर परिणाम पाया जा सकता हैं।

मदनलाल मीणा, व. अध्यापक
राजकीय उमावि. चिड़िया,
उपखंड गिड़ा,
जिला बाड़मेर, राजस्थान ।

नेटवर्क भी सुधारे दूरसंचार कंपनियाँ

मोदी सरकार देश को डिजिटल लेनदेन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रयत्नशील है। डिजिटल लेनेदेने के लिए मोबाइल दूरसंचार कंपनियों का नेटवर्क भी उचित होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट की धीमी गति ऑनलाइन लेनेदेन के लिए दिक्कत पैदा करती हैं। कुछ कंपनियों के घटिया नेटवर्क की समस्या उपभोक्ताओं के लिए ज्यादातर समस्या ही बना रहता है, कुछेक के तो 4जी इंटरनेट ऐसे चलता है, जैसे की 2जी। बेसक कंपनियाँ अपनेअपने नेटवर्क के मजबुत होने के दावे भी करती हैं, लेकिन यह दावे कभीकभी हकीकत की जमीन से बहुत दूर लगते है। खासतौर पर कुछ गाँवों और शहर के बाहरी क्षेत्रों में। हाल ही में दूरसंचार कंपनियों ने अपने टैरिफप्लानों में वृद्धि कर दी, इसकी बजह इन्होंने अपने को होने वाले आर्थिक नुकसान और सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए होने वाले भारी खर्चा होना बताया, यह तो उचित और दूरसंचार कंपनियों का हक है कि वो अपने काम के दाम बढ़ाएँ, लेकिन ये कंपनियाँ अपने मोबाइल नेटवर्क को देश के कोने कोने में स्ट्रांग करने के लिए गंभीरता क्यों नहीं दिखाती? ट्राई को इस बारे कुछ सोचना चाहिए, ताकि दूरसंचार कंपनियों के कमजोर नेटवर्क से लोगों से मुक्ति मिल सके और दाम के बदले उचित सेवाएँ दूरसंचार कंपनियों की मिल सके।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर

400 छक्के, पहले भारतीय बल्लेबाज बने रोहित

इंटरनैशनल क्रिकेट में 400 छक्के, गेल-अफरीदी के खास क्लब में शामिल हुए रोहित

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

मुंबई । टीम इंडिया के उपकप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बुधवार को एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर हैं।

रोहित से पहले इस फेहरिस्त में वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का नाम है। गेल ने अपने कुल 462 इंटरैनशनल मैचों में 534* छक्के जड़े हैं वहीं शाहिद अफरीदी ने 524 मैच खेलकर 476 छक्के अपने नाम किए हैं। इंटनैशनल क्रिकेट में सर्वाधिक सिक्स जड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रोहित

शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर के 354वें मैच की 360वीं पारी है । रोहित अभी तक 52 टेस्ट, 218 वनडे 103 टी20 इंटरनैशनल मुकाबले खेल चुके हैं। अपने 104वें मैच खेल रहे रोहित ने शेलडन कॉटरल की गेंद पर सिक्स लगाकर यह उपलब्धि हासल की।

इंटरनैशनल क्रिकेट में सर्वाधिक सिक्स लगाने के मामले रोहित 399 छक्कों के साथ पहले से ही तीसरे स्थान पर थे लेकिन 400 सिक्स के खास क्लब में शामिल होने से वह एक छक्का दूर थे।

सर्वाधिक इंटरनैशनल सिक्स जड़ने की फेहरिस्त में न्यू जीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैककुलम 398 छक्कों के साथ चौथे पायदान पर हैं। भारत के लिए सर्वाधिक सिक्स जड़ने की बात करें तो फिर रोहित शर्मा के बाद इस फेहरिस्त में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है। धोनी ने अब तक खेले 538 मैचों में 359 छक्के लगाए हैं। सचिन तेंडुलकर भारतीयों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। सचिन ने 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 264 छक्के लगाए हैं।

चुलबुल पांडे के फिल्टर ने सोशल मीडिया पर मचाया कोहराम

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। दबंग 3 के साथ चुलबुल पांडे की वापसी के लिए अब दस दिनों से भी कम समय बचा है, ऐसे में दर्शक इस फिल्म के साथ मनोरंजन के ट्रिपल डोज का बेसब्री से इंतजार कर रहे है।

एक तरफ जहां फिल्म के ट्रेलर और गाने ने सभी का ध्यान आकर्षित किया हुआ है, वही सोशल मीडिया पर चुलबुल का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। इससे पहले, निर्माताओं ने चुलबुल पांडे के जीआईएफ और स्टिकर जारी किए थे, जिसके जरिए उनके विभिन्न मूड को सिग्नेचर स्टाइल के माध्यम से दर्शाया गया था। अब, मेकर्स दर्शकों को चुलबुल जैसा बनने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने रॉबिनहुड पांडे के दिल के आकार वाले चश्मे के साथ दबंग 3 फिल्टर लॉन्च किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उपयोगकर्ता अपने सिर को

झटकता है तो चश्मा घूम कर सिर के पीछे पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि चुलबुल फिल्म में अपना चश्मा घुमाते है। इस तकनीक के जरिए, उपयोगकर्ताओं को चुलबुल की तरह बनने और उनके स्वैग का आनंद लेने का एक अनूठा मौका पेश किया गया है। बॉलीवुड में पहली बार, एक प्रमोशनल फिल्टर फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तीनों पर एक साथ लाइव होगा। जबकि दर्शकों को दबंग फिल्टर खूब रास आ रहा है, वही सबसे पहले चुलबुल पांडे ने खुद फिल्टर के साथ अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इतना ही नहीं, रज्जो और खुशी ने भी अपने सोशल मीडिया पर फिल्टर के साथ वीडियो पोस्ट किए है। दबंग 3 बॉलीवुड की सफल दबंग फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसमें सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा , अरबाज खान और किचा सुदीप मुख्य भूमिका निभा रहे है। वही, दबंग 3 के साथ महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही है। यह फिल्म प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान, अरबाज खान तथा निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित है जो 20 दिसंबर 2019 में रिलीज के लिए तैयार है।

भारतीय एकदिवसीय टीम में चोटिल धवन की जगह मयंक अग्रवाल शामिल

नई दिल्ली। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की आगामी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए चोटिल शिखर धवन के विकल्प के तौर पर बुधवार को भारतीय टीम में शामिल किया गया। धवन को सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के दौरान सूरत में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए बायें घुटने में गहरा कट लग गया था जिससे वह अब तक नहीं उबर पाए हैं। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से भी बाहर हो गए थे। बीसीसीआई ने बयान में कहा, ''बीसीसीआई की मेडिकल टीम का मानना है कि धवन के टांके कट गए हैं और उनका घाव भी भर रहा है लेकिन पूर्ण मैच फिटनेस हासिल करने से पहले उन्हें कुछ और समय की जरूरत है।'' इसमें कहा गया, ''अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में चोटिल शिखर धवन के विकल्प के तौर पर मयंक अग्रवाल को शामिल किया है।'' वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत तीन एकदिवसीय मैच चेन्नई (15 दिसंबर), विशाखापत्तनम (18 दिसंबर) और कटक (22 दिसंबर) में खेलेगा। अभी डिंडीगुल में तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्राफी मैच खेल रहे कर्नाटक के अग्रवाल चेन्नई में पहले मैच से पूर्व भारतीय

टीम से जुड़ेंगे। भारतीय टीम में फार्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल भी हैं जिन्हें उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ एकदिवसीय मैचों में पारी का आगाज करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में अग्रवाल को सीमित ओवरों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले अग्रवाल को इंग्लैंड में एकदिवसीय विश्व कप के दौरान चोटिल विजय शंकर के विकल्प के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। बेंगलुरू के अग्रवाल टेस्ट क्रिकेट में शानदार फार्म में हैं और नौ टेस्ट में तीन शतक और इतने ही अर्धशतक की मदद से 67 से अधिक के औसत से 872 रन बना चुके हैं। तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए भारत की संशोधित टीम इस प्रकार हैः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार।

नाडा के ब्रांड दूत के लिए कोई खिलाड़ी आदर्श पसंद होता

नई दिल्ली। भारत के शीर्ष युगल खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा का मानना है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को बालीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की जगह किसी खिलाड़ी को अपना ब्रांड दूत नियुक्त करना चाहिए था।

नाडा ने मंगलवार को शेट्टी को ब्रांड दूत के रूप में पेश किया और देश की डोपिंग रोधी एजेंसी को उम्मीद है कि उनके सेलीब्रिटी दर्जे से देश के खेलों को डोपिंग के दंश से दूर करने के उसके प्रयासों में मदद मिलेगी। ज्वाला ने यहां अपनी अकादमी के लांच के इतर कहा, ''मेरे अनुसार एक खिलाड़ी को नाडा का ब्रांड दूत बनाया जाना चाहिए था।''

उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि हम अभिनेताओं के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं।

समय आ गया है कि हम किसी खिलाड़ी को नाडा का ब्रांड दूत बनाएं। यह खेलों की महत्वपूर्ण संस्था है इसलिए मेरी नजर में खिलाड़ी आदर्श पसंद होता।''

बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह ने का कि खिलाड़ी अच्छी पसंद होते लेकिन उन्हें शेट्टी के इस भूमिका में आने से कोई परेशानी नहीं है।

ईद पर आमने-सामने आएंगी सल्लू-अक्की की फिल्में

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

मुंबई । साल 2020 में ईद के मौके पर सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्में एकदूसरे के आमने सामने आने वाली हैं। बता दें कि सलमान की 'राधे योर मोस्ट वांटेड भाई' अक्षय की 'लक्ष्मी बम' बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। हालांकि ईद के मौके पर रिलीज हो रही इन दोनों फिल्मों को लेकर अक्षय कुमार बयान दिया है कि हर साल सलमान ईद के मौके पर अपने फैंस के लिए फिल्म लेकर आते हैं। 2019 में भी उनकी 'भारत' भी ईद पर आई थी, जिसने 200 करोड़ से अधिक कलेक्शन किया था। इस बार भी ईद पर 'राधे योर मोस्ट वांटेड भाई' सिनेमाघरों में आने वाली है। हालांकि बीते दिनों उनकी इस फिल्म 'राधेयोर मोस्ट वांटेड भाई' का भी टीजर रिलीज हुआ था। सलमान खान के फैंस और सिनेमा प्रेमियों में फिल्म के टीजर को काफी पसंद किया था।

दरअसल, ईद पर पहले सलमान की 'इंशाअल्लाह' रिलीज होने वाली थी, जिसे संजय लीला भंसाली निर्देशित कर रहे थे, जबकि रोहित शेट्टी अपनी फिल्म सूर्यवंशी को ईद पर लाने का ऐलान कर चुके थे।

बॉक्स ऑफिस में होने वाली इस टक्कर से बचने के लिए उसी रिलीज मार्च में कर दी गई। वहीं, सलमान की 'इंशाअल्लाह' बंद हो गई। बता दें कि इंशाअल्लाह के हटने के बाद अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बम' को ईद पर रिलीज करने का ऐलान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अक्षय के सामने जब यह सवाल आया कि अगले साल वो ईद पर सलमान के सामने होंगे तो अक्षय ने कहा कोई भी आ सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पहले मैं आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि ईद का दिन है, दो फिल्में भी एक साथ आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकतीं क्या साथ में? वहीं जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म 'गुड न्यूज' बॉक्स ऑफिस पर 27 दिसम्बर को रिलीज होने वाली हैं। जिसे राज मेहता ने निर्देशित किया है। बता दें कि इस फिल्म में करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी मुख्य किरदारों में शामिल हैं।

'पति पत्नी और वो' की सफलता से भूमि खुश

नई दिल्ली। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज द्वारा बनी 'पति पत्नी और वो' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बता दें कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे मुख्य किरदारों में हैं। फिलहाल फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसे क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि फिल्म ने पहले वीकेंड में 33 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है। वहीं फिल्म को ऑडियंस से मिली तारीफों के बाद इसकी स्टारकास्ट सफलता को इंजॉय कर रही है। दरअसल बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर बात करते हुए हाल ही में भूमि ने कहा कि वह नंबर्स को ज्यादा समझ नहीं पाती हैं लेकिन उन्हें मालूम है कि 'पति पत्नी और वो' को हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म के एक सीन में उनके बोल्ड डायलॉग 'मुझे सेक्स बहुत पसंद है' पर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्हें इस डायलॉग को बोलते हुए अजीब नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत कहा कि उन शब्दों को बोलकर अजीब नहीं लगा क्योंकि उनका कैरक्टर आज के समय की लड़की का है।

धोनी के प्रशंसक प्रणव को अपने पसंदीदा क्रिकेटर से '183 आटोग्राफ' की चाहत

कोलकाता । भारत क्रिकेट और 183 के आंकड़े में काफी करीबी संबंध है और प्रशंसकों के पास इस संख्या को याद रखने के अपने कारण हैं। अधिकांश के लिए यह वह स्कोर है जिसका भारत ने 1983 विश्व कप में वेस्टइंडीज की मजबूत टीम के खिलाफ फाइनल में सफलतापूर्वक बचाव किया था। कुछ के लिए यह टानटन में विश्व कप में सौरव गांगुली की एतिहासिक पारी का स्कोर है। लेकिन बेंगलुरु के प्रणव जैन के लिए लिए 183 का मतलब महेंद्र सिंह धोनी के करियर की सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय पारी है और 22 साल के प्रणव का मिशन भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक के 183 आटोग्राफ हासिल करना है। कोलकाता आने से पहले ही प्रणव 153 आटोग्राफ हासिल कर चुके हैं। कोलकाता के रिसार्ट में धोनी के शूट पूरा करने का इंतजार कर रहे प्रणव ने कहा, ''माही भाई ने मुझे 183 आटोग्राफ का वादा किया है लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने मुझे कहा है कि 'जिस दिन तेरे 183 आटोग्राफ पूरे होंगे, तुझे और आटोग्राफ नहीं मिलेंगे'। मेरी आज 10 आटोग्राफ लेने की योजना है।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में न्यूजीलैंड की कड़ी परीक्षा

पर्थ । बेहतरीन फार्म में चल रहे न्यूजीलैंड की सफलता की असली परीक्षा गुरुवार से यहां दिनरात्रि टेस्ट के साथ आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की श्रृंखला में होगी। हाल में अपनी सरजमीं पर इंग्लैंड को हराकर लगातार सातवीं श्रृंखला में अजेय रही न्यूजीलैंड की टीम विश्व टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस प्रदर्शन और कप्तान केन विलियमसन, बल्लेबाज रोस टेलर और टाम लैथम तथा गेंदबाज नील वैगनर के व्यक्तिगत फार्म के कारण विशेषज्ञ मौजूदा टीम को न्यूजीलैंड की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम कह रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के किसी भी खिलाड़ी ने पर्थ, मेलबर्न या सिडनी में कोई मैच नहीं खेला है जो कल से शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला के तीन आयोजन स्थल हैं और जब तक टीम यहां सफलता हासिल नहीं करती तब तक उसे वास्तव में न्यूजीलैंड की सर्वश्रेष्ठ टीम का दर्जा नहीं मिल पाएगा।न्यूजीलैंड ने आस्ट्रेलिया में एकमात्र टेस्ट श्रृंखला 1985 में जीती जब रिचर्ड हैडली और मार्टिन क्रो की अगुआई में टीम ने एतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 32 साल में न्यूजीलैंड की टीम आस्ट्रेलिया में 22 में से एक ही टेस्ट जीत सकी और कुल मिलाकर टीम ने

आस्ट्रेलिया में 31 में से तीन ही टेस्ट जीते हैं। आस्ट्रेलिया ने अपनी सरजमीं पर 2015 में हुई पिछली श्रृंखला में न्यूजीलैंड को 20 से हराया जबकि 2016 में न्यूजीलैंड को उसकी सरजमीं पर भी 20 से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड अगर आस्ट्रेलिया और इसके बाद स्वदेश में दुनिया की नंबर एक टीम भारत को भी हरा देता है तो नंबर एक टीम बन जाएगा। लेकिन उसकी राह आसान नहीं होगी। पाकिस्तान को स्वदेश में 20 से रौंदने वाली आस्ट्रेलिया की टीम शानदार लय में है। बल्लेबाजी में डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन का बल्ला ढेरों रन उगल रहा है जबकि मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की गेंदबाजी बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा रही है। न्यूजीलैंड की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उसे इन हालात में खेलने का कोई अनुभव नहीं है जबकि दौरे से पहले उसे अभ्यास मैच भी खेलने को नहीं मिला। इसके अलावा टीम ने पिछले कुछ समय से दिनरात्रि टेस्ट भी नहीं खेला है।

गोपीचंद के हितों के टकराव की जांच होनी चाहिएः ज्वाला

नई दिल्ली। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को यहां उनसे जुड़े हितों के टकराव के मुद्दे की जांच की मांग की। ज्वाला ने 'ज्वाला गुट्टा एकेडमी आफ एक्सिलेंस' के लान्च के मौके पर कहा, '' वह (गोपीचंद) मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता है। उनकी अपनी अकादमी है, जिला संघ के अध्यक्ष, तेलंगाना संघ के सचिव, खेलों इंडिया का हिस्सा, पीबीएल का हिस्सा, गोस्पोर्ट्स में भागीदार हैं। ये सारी चीजें कागजों पर उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर हितों के टकराव का मुद्दा है तो सवाल करिये।'' ज्वाला ने राष्ट्रीय शिविर का आयोजन सिर्फ गोपीचंद अकादमी में कराने पर भी सवाल उठाये। उन्होंने कहा, '' पहले मैंने बेंगलुरु, जालंधर जैसी कई जगहों पर शिविर में हिस्सा लिया लेकिन 2006 के बाद यह सिर्फ हैदराबाद स्थित गोपीचंद अकादमी में होता है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं क्योंकि मैं वहीं रहती हूं। लेकिन यह सही नहीं है।

बहुत सोच-समझ कर फिल्में बनायेंगी दीपिका

मुंबई। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण का कहना है कि वह बहुत सोंचसमझ कर फिल्मों का निर्माण करेंगी।दीपिका पादुकोण ने फिल्म 'छपाक' से एक निर्माता के तौर पर डेब्यू किया है। दीपिका ने बताया कि अब आगे वह फिल्मों के निर्माण का चुनाव किस तरह करेंगी। दीपिका से सवाल किया गया कि एक निर्माता के तौर पर वह अपने प्रॉडक्शन में किस तरह की फिल्मों का निर्माण करेंगी।

इस समय 'छपाक' के अलावा और कौनकौन सी फिल्में हैं? जवाब में दीपिका ने कहा, 'मैं अपने प्रॉडक्शन हाउस में अंधाधुन फिल्मों का निर्माण नहीं करना चाहती, मैं फिल्मों का प्रॉडक्शन प्रॉपर ढंग से देखसमझ कर करूंगी, जैसे एक ऐक्टर के तौर पर मैं फिल्म की स्क्रिप्ट का चुनाव करती हूं, ठीक ऐसा ही प्रॉसेस फिल्म प्रोड्यूस करने का होगा।'दीपिका ने कहा,मैं यहां पर बैठकर एक अनुभवी निर्माता की तरह बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे फिल्मों के निर्माण का अनुभव नहीं है। मैं यहां सीखसमझ कर फिल्म निर्माण में अपना सहयोग देने के लिए हूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं जताऊंगी मुझे सबकुछ आता है, मैं यह भी जानती हूं कि इस दौरान मुझसे गलतियां भी होंगी। फिल्मों के चुनाव में मेरा इरादा ठीक वैसा ही रहेगा, जैसा एक ऐक्टर के तौर पर रहा है।

सॉरी आई एम लेट मेरी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म हैः निकिता सोनी

मुंबई । एक्ट्रेस निकिता सोनी एक बार फिर मेट्स एंटरटेनमेंट की डार्क थ्रिलर फिल्म सॉरी आई एम लेट में नजर आने वाली है। निकिता का कहना है कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। निकिता सोनी मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म सॉरी आई एम लेट की लॉन्चिंग के दौरान मीडिया के साथ बातचीत कर रही थीं। फिल्म में महाअक्षय चक्रवर्ती अंकिता ठाकुर और मुजाहिद खान भी लीड रोल में है।

निकिता सोनी ने मेट्स एंटरटेनमेंट के साथ अपने कोलाबोरेशन के बारे में बात करते हुए कहा में मेट्स एंटरटेनमेंट के साथ बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हूं। यह अब मेरे लिए एक घर की तरह हैए जैसे मैं वहाँ की बच्ची हूँ और वो प्रोडक्शन हाउस मेरी माँ है। मैंने इस प्रोडक्शन के साथ अपनी डेब्यू फिल्म आई नो यू भी की है। और अब मैं अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म पर काम करने जा रही हूं।

फिल्म की अनाउंसमेंट अभी हाल ही में हुई हैए इसका टाइटल है सॉरी आई एम लेट। मैं इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने में काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही हूं क्योंकि यह मेरे लिए एक परिवार की तरह है और मैं फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हूं।

सॉरी आई एम लेट एक डार्क थ्रिलर फिल्म है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म के कॉन्सेप्ट और फिल्म के यूनिक टाइटल के बारे में बात करते हुए निकिता ने कहा मूवी का टाइटल बहुत ही अनोखा है। सॉरी

आई एम लेट एक ऐसा शब्द है जिसे लोग यकीनन दिन में एक बार तो बोलते ही है। लेकिन इसे अभी तक फिल्म के टाइटल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।

निकिता इस फिल्म में पहली बार महाअक्षय के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी और वह इसे लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा मैं इस फिल्म में महाअक्षय चक्रवर्ती के साथ काम कर रही हूंए इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड और खुश हूं। मिमोह एक अच्छे एक्टर हैंए उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया हैए इसलिए उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखने का इंतजार कर रही हूं। मैं फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। फिलहाल अभी हम वर्कशॉप कर रहे हैं। अपनी किरदार के बारे में बात करते हुएए निकिता ने कहाए श्मेरे कैरेक्टर का नाम रोनिका है। वह आत्मनिर्भर है और किसी की नहीं सुनती है। यह मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल हैए इसलिए मैं अपने किरदार के लिए काफी मेहनत कर रही हूं।अपने कैरेक्टर के लिए मैं फिजिकल ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। मैं इन दिनों जिम में वर्कआउट कर रही हूं और साथ ही डाइटिंग भी करती हूं। फिल्म को मेट्स एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और इसे जयवीर पन्हाल डायरेक्ट करेंगे।

बिग बैश से ज्यादा मजेदार है बांग्लादेश प्रीमियर लीग

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

लंदन । टी20 क्रिकेट में जब भी प्रीमियर लीग की बात आती है तो आईपीएल का नाम सबसे पहले आता है. आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे लोकप्रिय और कामयाब टी20 लीग है. आईपीएल की ही तरह बिग बैश लीग और बॉग्लादेश प्रीमियर लीग होती है. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, आईपीएल के बाद दूसरी सबसे कामयाब लीग है, जिसमें दुनियाभर के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं. लेकिन वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल का मानना है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग से ज्यादा मजेदार है।

आंद्रे रसेल टी20 के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है. वेस्टइंडीज का यह ऑलराउंडर लगभग हर बड़ी टी20 लीग में खेलता है और हर टीम उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है. आंद्र रसेल ने एक वेबसाइट से कहा, 'यह टूर्नामेंट (बांग्लादेश प्रीमियर लीग) ज्यादा मजेदार है. यह बिग बैश लीग से कम समय लगता है. इसलिए अपेक्षाकृत कम समय के लिए ही घर

से बाहर रहना पड़ता है. मुझे यहां बहुत प्यार मिलता है. यहां के लोग बहुत प्यारे हैं. मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप जब दुनिया के इस हिस्से में आते हैं तो आपका बड़े प्यार से स्वागत किया जाता है।

आंद्र रसेल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में राजशाही रॉयल्स के लिए खेलेंगे. रसेल इससे पहले कॉमिला विक्टोरियंस और ढाका डायनामेंट के लिए खेल चुके हैं।

रसेल ने कहा, 'मुझे टीम को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है.' बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सात टीमें हैं और एक सीजन में 46 मैच होते हैं। आंद्रे रसेल ने कहा, 'मैं ज्यादातर टीमों में बतौर खिलाड़ी ही रहा हूं. इसलिए मैं खुद को खिलाड़ी की ही तरह देखता हूं, जो अपनी टीम में महत्वपूर्ण होता है. खासकर वेस्टइंडीज के बाहर मैंने टीमों की कप्तानी नहीं की है. मैंने जमैका तलावाह की कप्तानी की है. अब मुझे राजशाही रॉयल्स में यह भूमिका मिली है. यह बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उम्मीदों पर खरा उतरूं।

रवीना टंडन ने भी बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर निकाली भड़ास

नई दिल्ली। मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने मंगलवार को कहा कि देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना जरूरी है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और फास्ट ट्रैक अदालतों की है जरूरत बलात्कार की घटनाओं को लेकर किये गये सवाल पर टंडन ने यहां संवाददाताओं से कहा, मैं समझती हूं कि (बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश के लिये) राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिये और फास्ट ट्रैक अदालतों की योजना को बहुत जल्द अमली जामा पहना दिया जाना चाहिये।

मेकअप कलाकारों के कार्यक्रं में हिस्सा लेने आईं थीं रवीना उन्होंने कहा कि दिसंबर 2012 में दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार का वीभत्स मामला सामने आने के बाद से वह दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार संवाद कर रही हैं। टंडन, मेकअप कलाकारों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने इंदौर आयी थीं।

यो-यो हनी सिंह के गाने पर नेहा कक्कड़ ने मचाया धमाल

मुंबई, (वेबवार्ता)। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ की आवाज को जितना पसंद किया जाता है उतनी ही ज्यादा उनकी लाइफ परफार्मेंस पापुलर होती हैं। बता दें कि बाकी सेलेब्रिटीज की तुलना में वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इसी के चलते उनके एक नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। जिसने सोशलमिडिया पर जमकर हंगामा मचा दिया है, यह कुछ ही घंटों में यह वीडियो उनके फैंस के बीच वायरल हो गया है। हालांकि नेहा हमेशा ही अपनी आवाज से स्टेज पर छा जाती हैं लेकिन इस वीडियो में वह फेमस रैपर यो यो हनी सिंह के गाने पर धूम मचा रही है। इस वजह से उनका ये नया अंदाज उनके फैंस के साथ यो यो के फैंस को भी वीडियो बारबार देखने के लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल इस वीडियो में नेहा अपने अलग ही अंदाज में 'चार बोतल वोदका' गाती नजर आ रही हैं। उनके इस नए वीडियो को उनके फैन पेज से शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर किए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं,

लेकिन काफी तेजी से इसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में नेहा कक्कड़ एक विवाद के चलते सुर्खियों में आई थीं, दरअसल कॉमिक एक्टर गौरव गेरा और कीकू शारदा उनका मजाक उड़ाते नजर आए थे। जिसके बाद नेहा ने अपने कद, चेहरे की बनावट और आवाज को लेकर बनाए मजाक पर दोनों को जमकर फटकार लगाई थी।

एक नजर

तुराबनगर में दुकानों में तोड़फोड़ पर हंगामा, कई गिरफ्तार

गाजियाबाद । शहर के प्रमुख बाजारों में शुमार तुराब नगर में फिर बवाल होतेहोते रह गया। व्यापारी नेताओं ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले को कंट्रोल में किया। हुआ यूं कि तुराब नगर के मेन बाजार में एक दुकान मालिक के बुलाने पर आये कुछ लोग रात करीब दस बजे जेसीबी मशीन से कुछ दुकानों को तोडने लगे। इन दुकानों को वर्षों से किराए पर दिया गया था। बिना बताए ही जेसीबी मशीन से इन दुकानों को तोड़ा जाने लगा। जिन्होंने इन दुकानों को किराए पर ले रखा था, पता चलते ही वे मौके पर पहुंच गए और दुकानों को तोडने का विरोध करने लगे। इस पर जेसीबी मशीन के साथ आए लोगों की उनसे तूतूमैंमैं हो गई। थोड़ी ही देर में बात बिगड़ गई और मारपीट की नौबत तक आ गई। दुकानदारों का आरोप है कि दुकान मालिक ने भाड़े के गुंडों से उन्हें पिटवाया और परिवार समेत खत्म करने की धमकी दी। दुकानदारों का कहना है कि वहां तैनात चैकीदारों को भी भगा दिया गया। हंगामा होते देख दूसरे दुकानदार भी अपनीअपनी दुकानें बंद कर मौके पर पहुंच गए और विरोध किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जेसीबी मशीन, उसके चालक, जगमोहन भोला, रामअवतार भोला, मनीष भोला और शिव भोला को कोतवाली ले गई। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि ये लोग शराब पिए हुए थे। पुलिस आती देख, जेसीबी के साथ आए कई अन्य भाग खड़े हो गए। खिलाफ गैरकानूनी तरीके से दुकानों में तोडफोड़ और जान से मारने की धमकी की तहरीर दी गई। व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष गोपीचंद ने बताया कि घटना के तुरंत बाद व्यापारियों के एक दल ने कोतवाली में थानाध्यक्ष से मुलाकात की।

स्कूल बस और ट्रक की आमने- सामने भिड़ंत में 5 स्कूली छात्रों संग 7 घायल

भदोही । उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बुधवार की सुबह एक स्कूल बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हों गई। बस में सवार पांच बच्चों सहित बस का चालक घायल हो गया। गम्भीर रूप से घायल एक बच्चे और चालक को रेफर कर दिया गया है। अन्य बच्चो का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

भदोही कोतवाली क्षेत्र के भदोही सुरियावां मार्ग के नेवादा में सुबह करीब आठ बजे के करीब हुई जब वुडवर्ड पब्लिक स्कूल की बस बच्चो को लेकर स्कूल जा रही थी उसी दौरान सामने से आ रही एक सीमेंट लदी ट्रक से सीधी टक्कर हो जाने पर हड़कम्प मच गया। बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह छतिग्रस्त हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गयी और अफ़रा तफरी मच गया।बस में सवार बच्चो में प्रज्ञा दुबे, इशांत उपाध्याय, आयुष गुप्ता, प्रतीक्षा वर्मा और सलमान के साथ ट्रक चालक तलवार सिंह घायल हैं। पांच बच्चों के साथ बस का चालक भी गम्भीर रूप से घायल हो गया। बस चालक के मुताबिक सामने से आ रही ट्रक गलत दिशा में आ रही थी जिसके कारण यह घटना हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले के आवश्यक कार्यवाई में जुटी रही।

शिक्षा से ही आएगी समाज में समानता : आदित्यनाथ

पूरे देश में होनी चाहिए एक समान शिक्षा, गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे : योगी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामाजिक समानता के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी हथियार है। ऐसा तभी संभव है जब सबके लिए शिक्षा एक समान हो। शिक्षा समान होगी तो इसे हासिल करने वाले बच्चे भी एक समान होंगे। लिहाजा पूरे देश में एक समान शिक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है।

बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित स्कूल समिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य और समाज के लिए शिक्षा सबसे बुनियादी जरूरत है। पूरे देश में यह एक समान हो। इसके लिए सभी राज्यों में सहमति बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जरूरत है।

शिक्षा को दायरे में न बांधे

योगी ने कहा कि शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें किताबी ज्ञान से लेकर, संस्कार, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण तक शामिल है। इसे सीमित करना समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनने जैसा है। राज्यों, उनके विभिन्न बोर्डों और संस्थाओं के समाज और राष्ट्र के हित में एक समान और गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे। यह काम सिर्फ सरकारों के भरोसे संभव नहीं है।

लिहाजा शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को इसमें बढ़चढक़र सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। सबको मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार

करने होंगे जिसमें ज्ञान के साथ संस्कार और विद्यार्थी की क्षमता और रुचि के अनुसार स्वावलंबन का व्यावहारिक ज्ञान भी मिल सके। इस काम को मिशन के रूप में करना होगा।

सपा ने शिक्षा के स्तर को गर्त में पहुंचाया था

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की कार्यप्रणाली के कारण शिक्षा गर्त में पहुंच गयी थी। बच्चों को पास कराने के लिए नकल माफिया ठेके लेते थे।

राज्य और शैक्षणिक संस्थान समाज और देश हित में इसके लिए करें पहल

नकल करने वाले अच्छे नंबरों से पास होते थे और प्रतिभाएं कुंठित होती थीं। मार्च 2017 में जब भाजपा सत्ता में आयी तो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव के लिए हमने ऑपरेशन कायाकल्प और स्कूल चलो जैसे विशेष अभियान चलाए। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और कॉरपोरेट सेक्टर ने 1 लाख 58 हजार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में से 90 हजार से अधिक स्कूलों को कान्वेंट स्कूलों की बराबरी में ला दिया। इनमें स्मार्ट क्लासेज के जरिये बच्चों को शिक्षा दी जा रही है।

कीनन सबकी मदद से यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हम सारे स्कूलों का कायाकल्प नहीं कर लेते। प्राइमरी शिक्षा की इस बुनियाद को हम मजबूत कर ले गये तो उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चे अपना भविष्य स्वयं बना सकते हैं।

हमें विश्वास है कि इस आयोजन के जरिए हम सब एक कार्ययोजना बनाकर शिक्षा की एकरूपता के लिए सार्थक पहल कर समर्थ और सशक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार कर सकेंगे। देश, काल और हालात के अनुसार शिक्षा किस रूप में उपयोगी हो सकती है, इस पर चिंतन एक चुनौती है, पर मुकम्मल नतीजे पर पहुंचकर प्रभावी योजना बनाने और उसे अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी भी है।

क्षेत्र के सभी नेटवर्क ध्वस्त सम्बंधित अधिकारी मस्त

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

बहराइच । विकास खण्ड क्षेत्र बिशेश्वरगंज अंतर्गत मोबाइल नेटवर्क की बदहाल व्यवस्था पर संबंधित अधिकारियों द्वारा महीनों से कार्यवाही सुनवाई के शब्दों के साथ अब सही हो जाने की सफाई पेश की जा रही है, कमियों को दुरुस्त किये जाने का दावा किया जा रहा है उसके बाद भी क्षेत्र के सभी मोबाइल नेटवर्क अस्तव्यस्त चल रहा है। काल दर महंगा हो जाने के बावजूद नेटवर्क सेवा बेहतर के बजाय बदतर हो गया है ।देर से कॉल मिलने और कॉलड्राप होने की शिकायतों के साथ यदि नंबर लग भी जाता है तो बात नहीं हो पाती है,जवाब में नेटवर्क एरिया से बाहर है या उपभोक्ता का नंबर आउट ऑफ सर्विस आदि बताया जाता है।

यही नही पैकेज में मिलने वाली इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हैं। स्पीड नहीं मिलने और डाउनलोड स्लो होने से ग्राहक परेशान हैं, स्थानीय स्तर पर कंपनी के प्रतिनिधि उनकी शिकायतों को अनसुना कर रहे हैं।क्षेत्र में सबसे अधिक नंबर जियो कंपनी के ही हैं कुछ उपभोक्ता जियो टावर लगने के

बाद उससे प्रभावित होकर अन्य कम्पनी के सिम को जियो में पोर्ट करा लिया है, प्रवक्ता राजकुमार शुक्ल नें बताया कि मैंने कई बार शिकायत की परंतु हर बार सही हो जाने का आश्वासन मिलता है ।

क्षेत्र के ध्वस्त नेटवर्क से परेशान उपभोक्ताओं में अन्नू मिश्रा चन्द्र प्रकाश अभिषेक कुमार पाठक शिवओम सुनील रक्षाराम यादव गंगा राम मौर्या विक्रम मिश्रा ननके वर्मा आदि लोगों ने ध्वस्त नेटवर्क से जल्द निजात न मिलने पर अन्य कम्पनियों में पोर्ट कराने की बात कही है । प्राप्त सूचनानुसार त्रस्त उपभोक्ताओं नें प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय से इस बावत शिकायत की , निरीक्षक नें मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित जिम्मेदारों से उक्त शिकायत को गंभीरता से लेने की बात की एवँ आक्रोशित उपभोक्ताओ को भी समझाया । बता दें कि अगर 6 महीनों से प्रकाशित खबर को क्लस्टर हेड करूणा रमन शर्मा संज्ञान में ले लेते तो आज प्रभारी निरीक्षक को जद्दोजहद न करनी पड़ती और निरीक्षक का समय निरर्थक न जाता । उपर्युक्त तथ्यों पर जियो रिलायंस क्लस्टर हेड करुणा रमन शर्मा समस्या का समाधान होने का लगातार महज़ दावा कर रहे हैं जबकि धरातल के पटल पर हकीकत कुछ और है ।

गैस सिलेंडर लीक होने से मकान में आग लगी

गाजियाबाद । साहिबाबाद स्थित पसोंडा गांव में बुधवार की सुबह रसोई गैस सिलेंडर लीक होने के कारण रसोई घर में आग लग गई जिसके कारण रसोई और मकान में रखा हुआ सामान जलकर गया काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। अख्तर पुत्र रियाजुद्दीन गांव मदीना मस्जिद पसोड़ा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुबह 11 बजे के लगभग उनकी पत्नी मुन्नी खाना बना रही थी।

गैस सिलेंडर में गैस खत्म हो गयी। कुछ दिन पूर्व में लिया गैस सिलेंडर घर में रखा हुआ था। गैस सिलेंडर बदलने के बाद गैस को जलाते ही सिलेंडर में आग लग गई। मुन्नी ने रसोई में शोर मचाया। लेकिन काफी प्रयास किया लेकिन दोनों के फोन नहीं लगे। अख्तर और आसपास के निवासियों ने मिलकर आग पर काबू पाई तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अख्तर ने आरोप लगाया कि एजेंसी द्वारा पूर्व में भी कई बार लीक सिलेंडर सप्लाई किये हैं।

नागरिकता विधेयक को न्यायालय में दी जायेगी चुनौतीः चिदंबरम

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने नागरिकता संशोधन विधेयक को पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुये बुधवार को राज्यसभा में कहा कि अब इस विधेयक को न्यायलय में चुनौती दी जायेगी तथा इस पर न्यायाधीश और वकील बहस के आधार पर फैसला करेंगे जो संसद के गाल पर तमाचा होगा। चिदंबरम ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आज सदन में पेश इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुये कहा कि भारत में नागरिकता को लेकर कानून है। इस देश में किस तरह से नागरिकता दी जायेगी इसका पूरा प्रावधान है लेकिन इस सरकार ने सिर्फ तीन देशों को एक समूह बनाकर वहां के अल्पसंख्यकों विशेषकर हिन्दु, सिख, ईसाई, बौद्ध और अहमदिया को नागरिकता दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि श्रीलंका के हिन्दुओं और भूटान के ईसाई को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस विधेयक की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुये कहा कि यह विधेयक न्यायपालिका में टीक नहीं पायेगा।

उन्होंने कहा कि जो काम विधायिका को करना चाहिए अब वह काम न्यायपालिका को करना होगा। जिनको कानून बनाने के लिए चुनकर भेजा गया है वे अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो गये हैं। अब इस विधेयक को न्यायलय में चुनौती दी जायेगी और इस पर न्यायाधीश और वकील बहस के आधार पर फैसला करेंगे जो संसद के गाल पर तमाचा होगा। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को लेकर वह सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जबाव कौन देगा। ऑटोंनी जनरल को सदन में बुलाकर इसका जबाव दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के अल्पसंख्यकों को ही क्यों इसके लिए चुना गया है।

इन तीनों देशों के सिर्फ हिन्दु, क्रिश्चन,सिख, बौद्ध, पारसी और अहमदिया को ही इसके लिए चयन किया गया है। इस्लाम और अन्य धर्माबंलियों का चयन क्यों नहीं किया गया है। भूटान के ईसाई और श्रीलंका के हिन्दुओं को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए धार्मिक उत्पीड़न को आधार क्यों बनाया गया है जबकि भाषा, राजनीतिक और कई अन्य कारणों से भी उत्पीड़न होता है। चिदंबरम ने कहा कि यह संविधान के तीन अनुच्छेदों के विरूद्ध है।

एनटीपीसी दादरी को बेस्ट फीचर स्टोरी के लिए प्रथम पुरस्कार

दादरी । एनटीपीसी दादरी को वित्त वर्ष 201920 के लिए वार्षिक नैगम संचार पुरस्कार 2019 के लिए फीचर स्टोरी श्रेणी में रामागुंडम के साथ प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार एन एन वर्मा, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन), एनटीपीसी द्वारा पंकज नरायण सक्सेना, प्रबंधक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस), एनटीपीसी दादरी को एनटीपीसी सीपत (छत्तीसगढ़) में दिसंबर 06, 2019 को आयोजित 30 वें नैगम संचार सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में दिया गया।

यह पुरस्कार न्यु इनिशियेटिव्स, बायो मास ब्लैंडिंग, म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट टू टोरीफाइड कोल, सीएसआर, बालिका सशक्तीकरण मिशन (जीईएम) 2019, एनटीपीसी दादरी की उपलब्धियों पर विशिष्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित फीचर स्टोरी पर दिया गया है।

कांग्रेस पर आरोप लगा CAB संग YSRCP

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली । जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि, संसद के ऊपरी सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान पार्टी सांसद ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि धर्म के आधार पर प्रवासियों को नागरिकता नहीं देना चाहिए।

राज्यसभा में बुधवार को विधेयक पर चर्चा के दौरान पार्टी विधायक वी.विजयसाई रेड्डी ने कहा कि सीएबी 2019 में उन धार्मिक अल्पसंख्यक प्रवासियों को नागरिकता देने की बात है जिनके अपने देश की स्थिति शांतिपूर्ण जीवन जीने की नहीं है और वे वहां प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लिहाजा हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी वाईएसआरसीपी सभी धर्मों का सम्मान करने में यकीन करती है और इसलिए हम केंद्र को सुझाव देना चाहते हैं कि उन प्रावधानों पर दोबारा विचार करे जिसके तहत धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात शामिल है। उन्होंने कहा कि

मॉइनॉरिटी के अंदर भी माइनॉरिटी होते हैं जो प्रताड़ना का शिकार हैं जैसे बोरा और अहमदिया मुसलमान। अगर भारत में नागरिकता के लिए ऐसे लोग आवेदन देते हैं तो उन्हें नागरिकता देने पर विचार करना चाहिए। वाईएसआरसीपी सांसद ने कैब की आलोचना करने पर कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक मूल्यों की बात करती हैं, लेकिन खुद तुष्टिकरण की राजनीति करती है। उन्होंने शाह बानो केस का उल्लेख करते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि उसके कार्यकाल में एक मुस्लिम महिला के साथ अन्याय हुआ। नागरिकता विधेयक बिल सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया और उसे आज ऊपरी सदन में पेश किया गया।

विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और साथ ही कहा कि देश के मुसलमानों को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इस विधेयक पर देश के अलगअलग हिस्से में विरोधप्रदर्शन का दौर जारी है। पूर्वोत्तर भारत में इस पर जबर्दस्त विरोध हो रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए त्रिपुरा में आर्मी की तीन टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जबकि असम में सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है।

बीएसएफ एडीजी सुरेन्द्र पंवार का दो दिवसीय भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा सम्पन्न

बीकानेर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एडीजी सुरेन्द्र पंवार के दो दिवसीय भारतपाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा बुधवार को सम्पन्न हो गए। अपनी दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बीकानेर की खाजूवाला व घडसाना के अन्तर्गत आने वाली भारतपाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया व संध्या में सीमा सुरक्षा बल परिसर अनुपगढ़ में पंवार के आगमन पर कमांडेंट के.गिरी द्वारा स्वागत किया गया व सीमा सुरक्षा बल की सुसज्जित गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अतिरिक्त महानिदेशक का सम्मान किया। इस दौरान पंवार के साथ राजस्थान सीमांत मुख्यालय के महानिरीक्षक अमित लोढा, उप महानिरीक्षक सामान्य कुंवर मदन सिंह राठौड, बीएसएफ के बीकानेर सैक्टर मुख्यालय के डीआईजी यशवन्त सिंह देवडा भी उपस्थित रहे। पंवार ने सीमा चौकियों पर तैनात अधिकारियों व जवानों से मुलाकात की तथा जवानों को ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं को सुना। सीमा चौकी पर पंवार ने सैनिक सम्मेलन लिया व सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व जवानों की हौसला अफजाई की।

सैनिक स्कूल के शिक्षक ने 12 बच्चों से किया कुकर्म, गिरफ्तार

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

जयपुर। राजस्थान में झुंझुनूं जिले के सैनिक स्कूल में तैनात एक शिक्षक द्वारा पिछले छह माह में एक दर्जन बच्चों के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। दस से बारह साल तक के बच्चों के साथ कुकर्म करने के बाद शिक्षक उन्हें किसी को बताने पर जान से मारने या परीक्षा में फेल करने की बात कह कर धमकाता रहा। शिक्षक के कुकर्म का दौर जारी रहा तो एक पीड़ित बच्चे ने पिछले दिनों स्कूल की शिकायत पेटी में अपनी पीड़ा लिखकर कागज डाल दिया। मामला स्कूल प्रिंसीपल तक पहुंचा तो उन्होंने गत सात दिसंबर को शिक्षक रविंद्र सिंह के खिलाफ झुंझुनूं की सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपित शिक्षक रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पॉक्सो में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच झुंझुंनू के पुलिस उप अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपित शिक्षक झुंझुनूं के ही जयपहाड़ी का रहने वाला है। उसका परिवार बीकानेर में रहता है और उसकी पत्नी भी बीकानेर में ही शिक्षिका है। आरोपित शिक्षक वर्तमान में दोरासर गांव स्थित स्कूल कैंपस में ही रहता है और यहीं

पर उसने बच्चों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों ने अपनी पीड़ा पहले भी शिकायत पेटिका में भी लिखित रूप में डाली थी, लेकिन शिक्षक ने उन्हें गायब कर दिया। शिक्षक को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

हरियाणा में पलवल के एक गांव की बेटी के साथ राजस्थान के भरतपुर जिले में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। राजस्थान के कामां थाने के अंतर्गत हुई घटना की सूचना जब लड़की के परिजनों को लगी वे पोस्टमार्टम कराकर शव को पलवल ले आए। मृतका के पिता ने छह नामजद सहित 10 आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, लूटपाट और हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार, मृतका के पिता ने आरोप लगाए हैं कि तीन युवक उसकी पुत्री का हथियारों के बल पर अपहरण कर ले गए। उसके बाद उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में हत्या कर दी। मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को जंगल में नीम के पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शव को मंगलवार देर रात्रि दफना दिया गया। मामले की पड़ताल जारी है।

थाना प्रभारियों को दिए रेप आरोपियों की निगरानी के निर्देश

गाजियाबाद । ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व जनपद के नोडल प्रभारी नरेन्द्र भूषण ने जिला मुख्यालय में कानून व्यवस्था व शासन की प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को उन्नाव जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए जमानत पर छूटे रेप आरोपियों की निगरानी रखने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों को दिए। नोडल प्रभारी ने कहा कि रेप मामलों में जमानत पर छूटे सभी आरोपियों की नियमित रूप से निगरानी की जाए। उनकी दिनचर्या पर नजर रखी जाए। तो वहीं पीड़िता व उसके परिजनों से भी नियमित रूप से मुलाकात की जाए ताकि पता चल सके कि आरोपियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित या धमकाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। नोडल प्रभारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी रेप पीड़िता को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध रूप से संचालित हो रही फैक्ट्रियों को सील जाए। घनी आबादी वाली इमारतों में चल रही फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए।

नागरिकता विधेयक पर तृणमूल कांग्रेस करेगी जनांदोलन

(वूमेन एक्सप्रेस ब्युरो)

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन विधेयक को भारत तथा बंगाल विरोधी और असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि इसे लेकर देश भर में संग्राम तथा जनांदोलन किया जायेगा और इसे देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी जायेगी। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए खुदीराम बोस और बाघा जतिन जैसे क्रांतिकारियों की दिसम्बर में जयंती का उल्लेख किया और कहा कि यह महीना बंगालियों के लिए बड़ा पवित्र होता है। इस पवित्र महीने में सरकार भारत और बंगाल विरोधी विधेयक लेकर आयी है। उन्होंने कहा कि अंडमान की जेल में बंद रहे क्रांतिकारियों में से 70 फीसदी बंगाली थे इसलिए सरकार बंगाल के लोगों को राष्ट्रभक्ति न सिखाये। इस विधेयक के खिलाफ संग्राम तथा जनांदोलन होगा और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जायेगी।

यहां हिरासत केन्द्र बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ पर झूठ बोलकर और यह कहकर, 'भारत खतरे में है', लोगों को भ्रम में डाल रही है। सदस्य ने कहा कि 'असत्य, झांसा और जुमला' पर आधारित सरकार कह रही है कि घुसपैठिये लोगों का अधिकार छीन रहे हैं लेकिन वह इस बात का जवाब नहीं देती कि उसकी नीतियों के कारण देश में दो करोड़ लोगों की नौकरी चली गयी। उन्होंने कहा कि यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक से लाखों लोगों को नागरिकता दी जायेगी लेकिन सरकार यह नहीं बताती कि संसद की एक स्थायी समिति के समक्ष गुप्तचर ब्यूरो के महानिदेशक ने ही बताया था कि लगभग 31 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार को वादे करने में माहिर बताते हुए उन्होंने कहा कि यह उन्हें तोड़ने में और भी अधिक माहिर है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारित होने से मोहम्मद अली जिन्ना का अधूरा काम पूरा हो जायेगा। ब्रायन ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370 को हटाने जैसे मुद्दों से तो देश जूझ ही रहा था अब लोगों को नागरिकता विधेयक पारित होने के बाद इसके परिणामों से भी जूझना होगा। तृणमूल नेता ने विपक्षी दलों विशेष रूप से जनता दल यू और बीजू जनता दल से विधेयक के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि आज तो आप यह विधेयक पारित करा देंगे लेकिन आने वाली पीढियों को क्या जवाब देंगे।

नैनी (इलाहाबाद) कार्यालय
मेवालाल की बगिया खादिम के बगल
प्रभारीः
राजेश सरकार
सुजीत चौरसिया
Mo- 9956762825
9451251066

वूमेन एक्सप्रेस

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुनील पाण्डेय ने आदित्य ग्राफिक्स INC, प्रताप भवन, 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–1 से मुद्रित व ई–4/168, गली नंबर–6, सागर मार्केट, साढे 4 पुस्ता, सोनिया विहार दिल्ली–94 से प्रकाशित किया।

RNI.DELHIN / 2013/ 48606

मो.– 07042999974
टेली– 09013 518 518
www.womenexpress.in
thewomenexpress@gmail.com

एक नजर

बेंगलुरू के स्टार्टअप निंजाकार्ट में निवेश करेंगी वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट

नई दिल्ली। अमेरिका की खुदरा कंपनी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने बुधवार को कहा कि वे दोनों संयुक्त तौर पर बेंगलुरू की आपूर्ति श्रृंखला कंपनी निंजाकार्ट में निवेश करेंगी। एक बयान में कहा गया कि तीनों कंपनियों का लक्ष्य देश भर में खुदरा विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले ताजे उत्पादों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही उनका लक्ष्य किसानों के लिये आर्थिक अवसरों का सृजन करना भी है। हालांकि कंपनियों ने निवेश की राशि की जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट इस सौदे के तहत निंजाकार्ट को उपभोक्ता दायरा बढ़ाने, नये शहरों तक पहुंचने और ताजे उत्पाद की स्थानीय पारिस्थितिकी की दक्षता विस्तृत बनाने के लिये वैश्विक स्तर के मानक अपनाने में भी मदद करेंगी। निंजाकार्ट इससे पहले टाइगर ग्लोबल, एस्सेल पार्टनर्स, स्टीडव्यू कैपिटल, सिंजेंटा वेंचर्स, क्वालकॉम वेंचर्स और इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन निलेकणि से निवेश जुटा चुकी है।

उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित होंगे ओडी,ओपी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पादों के विनिर्माण और विपणन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी इकाइयों की सुविधा हेतु 'एकजिला,एकउत्पाद' (ओडी,ओपी) संकुल स्थापित करायेगी। स्थानीय उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने की इस योजना की प्रगति पर उद्योग निदेशालय स्तर से बराबर निगाह रखी जाएगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केन्द्र सरकार के सहयोग से कुछ जिलों में ऐसे औद्योगिक संकुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्हें समय से पूरा किया जाय, ताकि उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को इसका लाभ समय से मिल सके। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल ने संकुल विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत सामान्य सुविधा केन्द्रों के निर्माण और क्रियान्वयन संबंधी कार्यों की समीक्षा के बाद एक बयान में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत संकुलों के निर्माण कार्य को तीव्र गति से पूरा किया जाय और केन्द्र सरकार से अवशेष धनराशि समय से प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि भदोही में आधुनिक कारपेट, उन्नाव में जरीजरदोजी, बरेली में रेडीमेड गारमेंट, वाराणसी में ग्लास बीडस् और अत्याधुनिक सिल्क विविंग तथा सोनभद्र में कालीन एवं दरी के क्लस्टर स्थापित किये गये हैं। जिनका इस क्षेत्र के उद्यमी और हस्तशिल्पी भरपूर लाभ ले रहें हैं। उन्होंने कहा कि इन संकुलों से प्रदेश में उद्योगों को जहां नई गति मिल रही है और उद्यमियों को बेहतर बाजार भी सुलभ हो रहा है। आगरा, मेरठ और फिरोजबाद जनपद में अवस्थापना विकास परियोजनाओं का उन्नयन किया जा रहा है।

सउदी अरामको ने 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ की शेयर बाजार में शुरुआत

रियाद । पेट्रोलियम कंपनी सउदी अरामको के शेयर का बाजार में तेजी के साथ स्वागत किया गया। कंपनी के रिकॉर्ड 25.6 अरब डॉलर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद इसका शेयर बुधवार को स्थानीय शेयर बाजार में पहले दिन के कारोबार की शुरुआत में 10 प्रतिशत की बढ़त पर था। इससे कंपनी की बाजार में शेयर मूल्य के हिसाब से हैसियत 1,880 अरब डॉलर तक पहुंच गयी। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से यह विश्व की किसी सबसे महंगी सूचीबद्ध कंपनी बन गयी है। अरामको ने रियाद के तदावुल शेयर बाजार में सुबह साढ़े 10 बजे कारोबार की शुरुआत की। अरामको ने आईपीओ की दर 32 रियाल यानी 8.53 डॉलर प्रति शेयर तय की थी और प्राथमिक बाजार में शेयर बेच कर 25.6 अरब डॉलर जुटाए। इस आईपीओ ने 2014 में अलीबाबा द्वारा के 25 अरब डॉलर के आईपीओ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सउदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी योजना अर्थव्यवस्था को कच्चा तेल पर निर्भरता से उबारना है। इसके तहत अरामको की 1.5 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी तीन अरब शेयरों को बेचने की पेशकश की गयी थी।

गांव-गांव तक पहुंचाएं नागरिक बिल की खूबियां

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की करतूत को जनता के बीच ले जाने की दी नसीहत

(विशेष संवाददाता)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सांसदों को सरकार के छह माह के कार्यकाल की उपलब्धियों और विपक्ष द्वारा पाकिस्तान की भाषा बोलने की असलियत को जनता के बीच ले जाने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में पहली बार भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया।

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य के साथ ही सरकार की छह माह की उपलब्धियों को जनता तक ले जाएं। साथ ही सांसदों को सुझाव दिया कि वे जगहजगह गांव गांव कार्यक्रम करें और लोगों को असलियत से रूबरू करवाएं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित पार्टी सांसदों ने हिस्सा लिया।

बैठक में सरकार की छह माह की उपलब्धियों पर प्रकाशित एक पुस्तिका भी वितरित की गई। इसमें प्रधानमंत्री ने देश में साढ़े पांच साल में हुए काम का देश की दिशा बदलने वाला बताया।

प्रधामनंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में भी देश में जागरूकता फैलाने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही कहा कि सांसद इस कानून से लाभ पाने वाले लोगों

से मिलें और उनके पक्ष को जनता के सामने लाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता विधेयक को लेकर विपक्षी दलों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया और कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

मोदी ने कहा कि पिछले छह महीने में सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने, अर्थव्यवस्था की मजबूती, किसानों सहित विविध क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य' किये हैं और पार्टी सांसद इन कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएं।

कहा- कुछ राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं

उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रताडना के कारण अपने देश से भागने पर मजबूर हुए लोग लम्बे समय से अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे और प्रस्तावित कानून के अमल में आने पर उन्हें स्थायी रहत मिलेगी।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि विधेयक को लेकर भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है और वे सब इसे उजागर करें। उनकी टिप्पणी को नागरिकता संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के विरोध के संदर्भ में देखा जा रहा है।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि यह देश को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा और यह धार्मिक प्रताडना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता, मुख्यमंत्री बी एस येदियुप्पा और प्रदेश नेतृत्व को बधाई भी दी।

मोदी ने कहा कि कर्नाटक उपचुनाव में हमारी पार्टी ने दो सीट ऐसी जीती हैं जिन्हें वह पहले कभी नहीं जीत पायी थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जीत के लिये हम सभी को प्रदेश की जनता का खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए।

उन्होंने पार्टी सांसदों से 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती अच्छे तरीके से मनाने को कहा। इसमें कहा गया है कि बड़े वादे पूरे किये, बड़ी उम्मीदों को छूआ।

भारतीय मुस्लिम भारतीय थे, हैं और रहेंगेः शाह

नई दिल्ली । गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक चर्चा एवं पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान भारतीय नागरिक थे, हैं और बने रहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए उच्च सदन में गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों के पास समान अधिकार नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 20 फीसदी कम हुई है। इसकी वजह उनका सफाया, भारत प्रवास तथा अन्य हैं। शाह ने कहा कि इन प्रवासियों के पास रोजगार और शिक्षा के अधिकार नहीं थे।शाह ने कहा कि विधेयक में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से आये हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा ने पारित किया।उच्च सदन में कई विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव दिया है।विधेयक पर चर्चा होने के बाद इसे पारित करते समय इन प्रस्तावों के बारे में निर्णय किया जायेगा।शाह ने इस विधेयक के मकसदों को लेकर वोट बैंक की राजनीति के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने 2019 के आम चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की थी और पार्टी को इसी पर जीत मिली थी।उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं और बने रहेंगे।

मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया है नागरिकता संशोधन विधेयक

नड्डा ने विपक्ष को राजनीतिक हितों के बजाय राष्ट्र के हित साधने की नसीहत दी

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया एक कदम बताते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष को राजनीतिक हितों के बजाय राष्ट्र के हित साधने की नसीहत दी और दावा किया कि तथा इससे पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा।

राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नड्डा ने कहा कि यह विधेयक बेहद परेशानियों में जीवन जी रहे लाखों लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार देते हैं। नड्डा ने राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 18 दिसंबर 2003 में दिये गये एक बयान का हवाला दिया। उस समय सिंह ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सलाह देते हुए कहा कि ऐसे प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के मामले में सरकार को अपने रवैये को उदार बनाना चाहिए और नागरिकता कानून में

बदलाव करने चाहिए। नड्डा ने दावा किया कि मनमोहन सिह की बात को पूरा करते हुए हमारी सरकार इस विधेयक का लेकर आयी है। पूर्वोत्तर की चर्चा करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पूर्वोत्तर में यह भ्रम फैलाया गया है कि इस क्षेत्र की सांस्कृति पहचान खत्म हो जाएगी। वहां लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस बात का पहले ही स्पष्ट आश्वासन दे चुके हैं कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद भी इनर परमिट' व्यवस्था जारी रहेगी। पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान बरकार रहेगी। उनके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं हुआ है। उन्होंने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस विधेयक के विरोध में कई ऐसे तर्क दिये हैं, जिनका मूल से संबंध नहीं है।'' इस विधेयक का एक ही आधार है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिन लोगों की धार्मिक आधार पर प्रताडना हुई हैं, उन्हें भारत में शरण लेने पर नागरिकता दी जाएगी। इससे पूर्व विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता शर्मा ने इस विधेयक को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के विरूद्ध बताया था। नड्डा ने कहा कि यह सच्चाई भले ही जितनी कड़वी हो पर सच बात यही है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय जितना नरसंहार हुआ और जितनी बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ गये, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यक थे। पाकिकस्तान में हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यक थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए नेहरूलियाकत अली समझौता हुआ था। ड्क्षकतु समझौते का पालन पाकिस्तान में नहीं किया गया। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार वह एक इस्लामिक राष्ट्र है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी मात्र दो प्रतिशत रह गयी है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भारत में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह स्थिति को समझना नही चाहती है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इंदौर, कच्छ या पश्चिम बंगाल में ऐसे शरणार्थियों के हालात जाकर देखना चाहिए।

कई वस्तुओं पर बढ़ सकती है जीएसटी दरें

राजस्व कमी को दूर करने के लिये सरकार ने लिया फैसला

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में जीएसटी की दर और स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। जीएसटी की अब तक की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं रही है। इसकी वजह से केन्द्र तथा राज्यों की राजस्व वसूली काफी दबाव में आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह 18 दिसंबर को बैठक होने वाली है। जीएसटी के सभी फैसले जीएसटी परिषद में ही लिये जाते हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि जीएसटी संग्रह उम्मीद से कम रहा है और कई राज्यों का मुआवजा भी लंबित है। राज्य उन्हें जल्द से जल्द इसकी भरपाई किये जाने की मांग कर रहे हैं। जीएसटी के तहत इस समय मुख्यतः चार दरें पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 और 28 प्रतिशत हैं। इसके अलावा 28 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली माल एवं सेवाओं पर उपकर भी लिया जाता है। यह उपकर एक से लेकर 25 प्रतिशत के दायरे में लगाया जाता है। केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों के एक समूह ने मंगलवार को बैठक कर जीएसटी दरों

को तर्कसंगत बनाने की अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप दिया। इसमें कई विकल्पों पर विचार किया गया जिनमें से एक यह है कि पांच प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाये। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाये जाने के मामले में विस्तृत प्रस्तुतीकरण जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान ही दिया जायेगा। इसके साथ ही अन्य मुद्दों के अलावा राज्यों की बढ़ती मुआवजा जरूरतों को देखते हुये परिषद की बैठक में कुछ और उत्पादों पर उपकर वसूले जाने पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। जानकार सूत्रों ने बताया कि परिषद की बैठक में जीएसटी दरों को आपस में विलय कर उनकी संख्या मौजूदा चार स्लैब से घटाकर तीन भी की जा सकती है। परिषद विभिन्न छूटों पर भी फिर से गौर कर सकती है और यह भी देखेगी कि क्या कुछ सेवाओं पर उपकर लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर की अवधि में केन्द्रीय जीएसटी प्राप्ति 2019 20 के बजट अनुमान से 40 प्रतिशत कम रही है। इस अवधि में वास्तविक सीजीएसटी संग्रह 3,28,365 करोड़ रुपये रहा है जबकि बजट अनुमान 5,26,000 करोड़ रुपये रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष 2018 19 में वास्तविक केन्द्रीय जीएसटी प्राप्ति 4,57,534 करोड़ रुपये रहा जबकि वर्ष के लिये अस्थाई अनुमान 6,03,900 करोड़ रुपये का लगाया गया था। इससे पहले 2017 18 में सीजीएसटी संग्रह 2,03,261 करोड़ रुपये रहा था। इस बीच देश की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पिछली 26 तिमाहियों में सबसे कम 4.5 प्रतिशत रह गई। विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन पिछली नौ तिमाहियों में सबसे कम रहने की वजह से यह गिरावट आई। इससे पहले 2012 13 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रही थी। बहरहाल, जीएसटी की प्रस्तावित बैठक काफी अहम हो सकती है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जीएसटी और उपकर की वसूली काफी कम रही है।

लोकसभा में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पेश

(विशेष संवाददाता)

नयी दिल्ली। विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोकसभा में बुधवार को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 और उससे संबंधित विधेयक पेश किया गया। निचले सदन में विधेयक पेश करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इसमें श्रम कानूनों की जटिलताओं को कम करने और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने की पहल की गई है। हमने विधेयक लाने से पहले मजदूर संगठनों से गंभीर चर्चा की। गंगवार ने कहा, इसके तहत 44 कानूनों को चार कानूनों में बदलने की महत्वपूर्ण पहल की गई है।'' विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संबंधी संधि के खिलाफ है और श्रम संबंधी वर्तमान उपबंध को कमतर करता है। उन्होंने कहा कि इसमें देश की कामकाजी श्रम शक्ति की अनदेखी की गई है और उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का ध्यान नहीं रखा गया है । तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि यह श्रम सम्मेलनों के तहत तय मानकों के अनुरूप नहीं है। इस विषय पर केंद्रीय स्तर के मजदूर संगठनों के साथ चर्चा नहीं की गई है। और कई कानूनों को

एक साथ जोड़कर इसे और जटिल बनाया गया है। उन्होंने मांग की कि इसे संसद की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी इसे स्थायी समिति को भेजने की मांग की। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जून 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसने सिफारिश की थी कि श्रम विधियों को औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा तथा कल्याण एवं कार्य स्थितियां समूहों के तहत रखा जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों पर तथा सरकार, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक में प्रस्तावित विधान लाने का निश्चय किया गया था। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित विधान अर्थात सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 प्रौद्योगिकी के उपयोग को आसान बनायेगी और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। विधेयक में कहा गया है कि नियम अवधि कर्मचारियों के फायदों का परिमाण व्यापक होगा और श्रम विधियों का अनुपालन करना सुगम होगा जो समानता की ओर एक बड़ा कदम होगा। यह अधिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देगा जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा संबंधित बीमा योजना का बीस या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले औद्योगिक स्थापनों तक विस्तार करने की बात कही गई है।

नानावती आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी क्लीन चिट

गुजरात 2002 दंगे : दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे

(विशेष संवाददाता)

गांधीनगर। नानावती आयोग ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने सदन में आयोग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के पांच साल और दंगों के 17 साल बाद सदन में पेश किया गया है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी टी नानावती और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अक्षय मेहता के आयोग ने कहा कि कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस प्रभावी नहीं रही क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे या वे हथियारों से अच्छी तरह लैस नहीं थे। आयोग ने 1,500 से अधिक पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया।'' साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग का गठन किया था। यह दंगे गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की दो बोगियों में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे जिसमें 59 कारसेवक' मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है, सभी सबूतों पर विचार करने के बाद आयोग ने पाया कि गोधरा घटना के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगे वास्तव में उन घटनाओं के बाद हुए थे।'' इसमें कहा गया है, गोधरा घटना के कारण ही हिंदू समुदाय का बड़ा वर्ग काफी आक्रोशित हो गया और आखिरकार उन्होंने मुस्लिमों पर तथा उनकी

संपत्तियों पर हिसक हमले किए। आयोग ने यह भी कहा कि उसे दंगों के संबंध में किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दल या ऐसे किसी संगठन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है, आयोग के समक्ष आए सबूतों के आधार पर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विहिप और बजरंग दल के स्थानीय सदस्यों ने अपनेअपने इलाकों में हुई घटनाओं में भाग लिया। आयोग ने कहा कि राज्य में गोधरा के बाद हुए दंगे पूर्व नियोजित या हिसा फैलाने के लिए नहीं हुए थे। उसने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ इन आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उसने गोधरा के बाद हुए दंगों पर आंख मूंद ली थी। आयोग ने तीन पूर्व आईपीएस अधिकारियों संजीव भट्ट, राहुल शर्मा और आर बी श्रीकुमार की विश्वासनीयता पर भी सवाल उठाए जिन्होंने आरोप लगाया था कि दंगों में राज्य सरकार की भूमिका थी। उसने कहा कि सबूतों को बारीकी से खंगालने के बाद यह कहना संभव नहीं है कि पुलिस की ओर से कोई लापरवाही बरती गई थी। हालांकि, यह काफी जरूरी था कि राज्य के पास अनुशासित पुलिस बल होना चाहिए था जो यह सुनिश्चित करता कि समाज का सामंजस्य एवं शांति भंग न हो। रिपोर्ट में कहा गया है, साम्प्रदायिक दंगों के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में सबूतों पर विचार करते हुए हमने पाया कि पुलिस की गैर मौजूदगी तथा उनके पर्याप्त संख्या में न होने से भीड़ का हिसा करने के लिए हौसला बढ़ा। आयोग ने अहमदाबाद शहर में साम्प्रदायिक दंगों की कुछ घटनाओं पर कहा, %%पुलिस ने दंगों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य, तत्परता नहीं दिखाई जो आवश्यक था। नानावती आयोग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच या कार्रवाई करने की सिफारिश की है। आयोग के गठन के बाद जांच या कार्रवाई रोक दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में मीडिया संयम के साथ काम करे और अगर वह अपनी हदें पार करती दिखे तो उसके खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहा कि मीडिया को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह घटनाओं के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण खबरें छापने और साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काने में शामिल न हो। आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर 2009 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। आयोग ने 18 नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में गुजरात उच्च न्यायालय में कहा था कि वह अगले विधानसभा सत्र में रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। वह पूर्व आईपीएस अधिकारी आर बी श्रीकुमार की जनहित याचिका पर जवाब दे रही थी जिसमें राज्य सरकार को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

राज्य के पूर्व डीजीपी श्रीकुमार ने नवंबर 2015 में मुख्यमंत्री पटेल को आवेदन देकर पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने नानावती आयोग के समक्ष हलफनामे दाखिल किए थे।